अवध की आवाज

www.avadhkaawaz.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्रकाशित

वर्ष–11 अंक–248 R.N.I.- UPHIN/2012/45127 लखनऊ शुक्रवार 6 जनवरी 2023 पृष्ठ – 4 मूल्य–3 रूपया

बैंकिंग जगत के दिग्गजों से मिले सीएम योगी, बोले- आइए साथ मिलकर बनाएं नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दो दिवसीय मुंबई दौरे पर बैंकिंग जगत के दिग्गजों से मुलाकात कर उन्हें संबोधित किया और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने के लिए उनका आह्वान किया।

लखनऊ। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के विकास में सहयात्री बनने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के बैंकिंग और वित्तीय जगत का आह्वान किया है। नए भारत के श्ग्रोथ इंजनश उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के बड़े लक्ष्य के साथ दो दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गुरुवार को बैंकिंग जगत के दिग्गजों की बैठक हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें संबोधित किया और कहा कि मुझे पता है कि आप सभी न केवल अपने बैंक पर नजर रखते हैं बल्कि हमारे उत्तर प्रदेश पर भी आपकी नजर है। आप वहां की हर खबर रखते हैं। आप हमारी विकास यात्रा के साक्षी भी हैं और सहभागी भी।

उत्तर प्रदेश आकार में भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य के साथ–साथ हम सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या वाले प्रदेश हैं। यह युवा हमारी ताकत है, हमारी पूंजी है। यहां की उर्वर भूमि हमारे प्रदेश की समृद्धि का अहम साधन है। 2017 में जब हमारी सरकार बनी तब प्रदेश की माली हालत बहुत खराब थी। हमने कुछ योजनाएं बनाईं, बैंकों को फोन किया, लेकिन क्रेडिट इतनी खराब थी कि बैंकों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया।

आज यह बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तब और अब के यूपी में सब बदल गया है। आज हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हैं। हमने अपने वार्षिक बजट को दोगुने से ज्यादा तक विस्तार दिया है। बीते 05–06 वर्षों के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क के माध्यम से बेहतर

कनेक्टिविटी के लिए त्वरित गति से बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है, जिससे उद्योगों को वैश्विक एवं घरेलू बाजार तक पहुंच बनाने में लॉजिस्टिक्स की सुलभता में वृद्धि होगी।

आज पूर्वी यूपी के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे है तो पिछड़े कहे जाने वाले बुंदेलखंड की तरक्की को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रफ्तार दे रहा है। पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र को जोड़ने के लिए हम प्रयागराज से मेरठ तक गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे राज्य के रूप विश्वस्तरीय रोड कनेक्टिविटी की उपलब्धता है।

उत्तर प्रदेश 05 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का एकमात्र राज्य बनने जा रहा है। हम लैंड लॉक स्टेट थे लेकिन अब यहां देश का पहला अंतर्देशीय जलमार्ग (इनलैंड वॉटर–वे), विकसित हो गया है। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश मे है। विकास और बदलाव के यह काम बिना बैंकों/वित्तीय संस्थानों के सहयोग के संभव नहीं था। आपने हमारा सहयोग किया, देखिए, उत्तर प्रदेश बदल गया।

प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराई

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कोरोना काल में जब प्रवासी श्रमिक आये तो लोगों ने हमसे कहा, इनको बुला रहे हैं, यह करेंगे क्या? हमने सबकी स्किल मैपिंग कराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से हमने प्रदेश के परंपरागत उद्यम की भी मैपिंग की और उस अनुसार कार्यक्रम बनाये तो आज 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां कार्यरत हैं जो करोड़ों युवाओं के सेवायोजन का माध्यम बनी हैं। एक जिला एक उत्पाद की जो हमारी अभिनव योजना है। हर जिले का अपना यूनिक उत्पाद है, हम उसकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग कर रहे हैं। यह योजना हमें अपने निर्यात को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है।

उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है तो हमारे सामने चुनौतियां भी बहुत हैं। ये चुनौतियां हमें अपने लिए बड़े लक्ष्य तय करने और कड़ी मेहनत के लिए प्रोत्साहित करती है। कोविड के लिए हमारी प्रबंधन नीति को विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित अनेक वैश्विक संस्थाओं ने सराहा है। तमाम चुनौतियों के बाद भी उत्तर प्रदेश आज पॉवर सरप्लस और रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने बड़े लक्ष्यों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है।

हम राज्य में अनेक औद्योगिक परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। भारत को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य के साथ स्थापित हो रहे दो डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में से एक का विकास उतर प्रदेश में किया जा रहा है। पहले के उत्तर प्रदेश में बेटियां शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थीं, असुरक्षा का माहौल था। आज मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में किसी बेटी को कोई बुरी नजर से देख नहीं सकता।

हमने ऐसा माहौल बनाया है कि आज उत्तर प्रदेश में किसी व्यापारी या कॉन्ट्रैक्टर से कोई गुंडा टैक्स नहीं वसूल सकता। यहां तक कि पॉलिटिकल चंदा भी जबरन नहीं लिया जा सकता। हमने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया। माफियाओं के अवैध कब्जे से भूमि खाली कराई। आज डिफेंस कॉरीडोर इसी भूमि पर बन रहा है। जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। आपने भट्टा–परसौल कांड सुना होगा। जमीन के लिए कितना विवाद हुआ! आज उसी भूमि पर वही किसान स्वेच्छा से एयरपोर्ट के लिए हमें भूमि दे रहे हैं।

यूपी को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री मोदी के 05 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य की पूर्ति में अपने लिए 1 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य आपके सहयोग से ही पूरा होगा। मैं आज आप सभी से यह कहने आया हूँ कि उत्तर प्रदेश में हम आपको हर संभव सहायता देंगे। हर से संसाधन देंगे। बेहतर माहौल देंगे। बैंकिंग संस्थाएं हमारी एमएसएमई इकाइयों, कृषि, एफ़पीओ, स्टार्टअप आदि को मजबूत बनाने के लिए हमें सहयोग दें।

पर्यटन भी एक प्राथमिक सेक्टर है, जिसके विकास में बैंकों का सहयोग अपेक्षित है। हमारी सरकार आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, बौद्ध सर्किट का विकास कर रही है। प्रधानमंत्री जी के विजन का साकार रूप भव्य काशी ने सभी को आनंदित किया है। दिव्य अयोध्या सपना भी पूरा हो रहा है।

यमुना एक्सप्रेसवे के निकट राज्य का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क का शुभारंभ किया गया है। इसी प्रकार यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में फिल्म सिटी, टॉय पार्क, अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक हब विकसित किए जा रहे हैं। अन्य परियोजनाओं में ग्रेटर नोएडा में आईआईटी जीएनएल, बरेली में मेगा फूड पार्क, उन्नाव में ट्रांसगंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, गोरखपुर में गारमेंट पार्क तथा अनेक फ्लैटेड फैक्ट्री परिसरों को विकसित किया जा रहा है।

हमने अपनी नीतियों में संरचनात्मक परिवर्तन करके एक प्रतिस्पर्धी, आकर्षक एवं सहायक प्रोत्साहन ढांचा प्रदान किया है। नई औद्योगिक नीति एक विकल्प आधारित मॉडल प्रदान करती हैं, जो उत्पादन, रोजगार एवं निर्यात को प्रोत्साहित करती है। सर्कुलर इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तथा ग्रीन हाइड्रोजन सहित नए क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

हमने सीडी रेशियो को 40 से बढ़ाकर 53% तक करने में सफलता पाई है, अब इसे 60: तक लाने में बैंकों को ठोस कोशिश करना होगा। हम अपनी ओर से हर तरह का योगदान करने को तत्पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश को देश के श्ग्रोथ इंजनश की सामर्थ्य वाला राज्य कहा है। हम अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं। आपके सहयोग से उत्तर प्रदेश लीडर स्टेट होगा। मैं आप सभी को हमारे राज्य विद्यमान अपार अवसरों का लाभ उठाने तथा नए भारत को समृद्ध एवं शक्तिशाली बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश की प्रगति यात्रा में हमारे साथ सहयात्री बनने के लिए उत्तर प्रदेश में आपको आमंत्रित करता हूं।

संक्षिप्त समाचार

07 जनवरी 2023 को अमर शहीद चन्द्र शेखर आजाद की 117 वी जयन्ती के आयोजन पर ग्राम बदरका उन्नाव में दो दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है।

अवध की आवाज ब्यूरो

उन्नाव। (सू0वि0) जिला सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि 06 जनवरी 2023 एवं 07 जनवरी 2023 को अमर शहीद चन्द्र शेखर आजाद की 117 वी जयन्ती के आयोजन पर ग्राम बदरका उन्नाव में दो दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है जिसमें लगभग 06 कम्पनियाँ, 725 रिक्त पदो पर चयन हेतु साक्षात्कार करेंगी। इच्छुक पुरूष/महिला अभ्यर्थी जो 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के हैं तथा शैक्षिक योग्यता कक्षा–10 से स्नातक तक है सेवायोजन की साइट पर लागिन करने के बाद पंजीकरण कर प्रतिभाग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के पटल सहायक से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

साध्वी निरंजन ने की ओबीसी आरक्षण पर सरकार की पहल की तारीफ

बीजेपी ही कर सकती है पिछड़ों और दलितों के अधिकारों की सुरक्षा : निरंजन ज्योति

लखनऊ/कानपुर। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पहुँची कानपुर और बीजेपी के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय में मीडिया से मुखातिब हुई। उन्होंने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई पहल की तारीफ करते हुए कहा कि दलितों, पिछड़ों के अधिकारों की सुरक्षा बीजेपी ही कर सकती है। साध्वी ने कहा कि सपा–बसपा वोट लेने तक सीमित है।सपा सैफई तक और बसपा अपने तक सीमित है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर दलित और मुस्लिम विरोधी का आरोप लगता है पर बीजेपी ने अब्दुल कलाम और रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया है और सर्वसमाज को आगे बढ़ाया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार में ओबीसी आयोग का गठन नहीं हुआ और बीजेपी ने ओबीसी आयोग बनाया। उन्होंने खुद पर बोलते हुए कहा कि खेत में फड़वा चलने वाले गरीब बाप की बेटी आज बोलने का साहस दिखा रही है। साध्वी निरंजन ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई पहल की जमकर तारीफ की और कहा कि दलितों, पिछड़ों के अधिकारों की सुरक्षा बीजेपी ही कर सकती है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर बोलते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि ये यात्रा कांग्रेस जोड़ो यात्रा है।कांग्रेस ने सरकार रहते गरीब को मकान नहीं दिया, उस वक्त जोड़ने का काम करना चाहिए था। भारत को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे गांव गरीब तक राशन पहुंचाया जाता है, पीएम मोदी कांग्रेस सीखे।

नगर निगम लखनऊ द्वारा नागरिको को सार्वजनिक स्थानों पर की रैन बसेरो व निराश्रितों को आश्रय की व्यवस्था

अवध की आवाज

लखनऊ। नगर निगम लखनऊ द्वारा नागरिको को सार्वजनिक स्थानों पर ठण्ड से बचाये जाने का दायित्व लेकर रैन बसेरो की व्यवस्था की गयी है। वर्तमान में नगर निगम लखनऊ द्वारा नगर के समस्त क्षेत्रो में 53 स्थाई/अस्थाई रैन बसेरे संचालित व क्रियाशील है जिसमें निराश्रितो को आश्रय की व्यवस्था हेतु सभी आवश्यक सुविधायें यथा–बेड, बिस्तर, नहाने के गर्म पानी हेतु गीजर, कमरे को गर्म रखने के लिये ब्लोवर, शौचालय की व्यवस्था एवं साफ–सफाई की अनिवार्य रूप से समुचित व्यवस्था करायी गयी है। नगर निगम लखनऊ की जोनवार टीम द्वारा रात्रि में सभी क्षेत्रो में भ्रमण कर सड़क/फुटपाथ पर सोये हुए व्यक्तियों को वाहनो में बैठाकर रैन बसेरो/शेल्टर होम में लेकर जाने का कार्य प्रतिदिन किया जाता है। वर्तमान में इन रैन बसेरो में 1453 व्यक्तियों द्वारा आश्रय प्राप्त किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आश्रयहीन, रैन बसेरो में ठहरे व्यक्तियों, रेलवे स्टेशनो के आगन्तुको, अस्पताल एवं चौराहो पर आने–जाने वाले व्यक्तियों को ठण्ड से बचाये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम लखनऊ द्वारा जगह–जगह कुल 1148 अलाव जलाये जाने की व्यवस्था अब तक की गई है। नगर निगम लखनऊ द्वारा दृढसंकल्पित होकर यह पूर्ण प्रयास किया जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में किसी भी नागरिक को शीत लहर/ठण्ड के कारण किसी समस्या का सामना न करना पड़े।

शहीद पथ की सर्विस लेन से हटाये गये अवैध अतिक्रमण

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर प्रवर्तन जोन–1 की टीम ने की कार्यवाही

अवध की आवाज

लखनऊ । लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गुरूवार को गोमती नगर विस्तार में अभियान चलाकर शहीद पथ की सर्विस लेन से अवैध अतिक्रमण हटवाये गये। इस क्रम में दुकानें, गुमटी, ठेले व झुग्गी–झोपड़ी समेत तीन दर्जन से अधिक अस्थायी अतिक्रमणों को ध्वस्त करके सड़क खाली करायी गयी। प्रवर्तन जोन–1 के जोनल अधिकारी अरूण कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार को उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आगामी जी–20 सम्मेलन के दृष्टिगत शहीद पथ का निरीक्षण किया गया था, जिसमें उनके द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त आदेश के अनुपालन में आज गोमती नगर विस्तार के सेक्टर–5 एवं 6 में अभियान चलाकर शहीद पथ की सर्विस लेन पर सड़क किनारे किये गये अतिक्रमणों को हटवाया गया। जिसमें सहायक अभियंता अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता इम्तियाज अहमद, सुभाष शर्मा व सुरेन्द्र द्विवेदी द्वारा प्राधिकरण पुलिस बल, गोमती नगर विस्तार थाने की पुलिस व पी0ए0सी0 बल के सहयोग से तीन दर्जन से अधिक अवैध अतिक्रमणों को हटाया गया।

अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने बीडीओ को सौंपा ज्ञापन

मांगों को पूरा करने के लिए दिया गया पीएम को सम्बोधित ज्ञापन

अवध की आवाज ब्यूरो

डुमरियागंज (सिद्धार्थ नगर) स अखिल भारतीय प्रधान संगठन ब्लॉक इकाई खुनियाँव द्वारा प्रधानमंत्री को सम्बोधित एक ज्ञापन बीडीओ खुनियाँव को देते हुए विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग की है। ज्ञापन में यह कहा गया है कि अखिल भारतीय प्रधान संगठन द्वारा रमाबाई अम्बेडकर मैदान में 28 अक्टूबर 2021 को 40,000 से अधिक प्रधानों की महारैली के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा गया था। जिसके क्रम में 15 दिसम्बर 2021 को प्रदेश भर के प्रधानों को लखनऊ बुलाकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न घोषणाएं की गयी थीं। जिन पर लोकहित में तत्काल अमल किया जाना आवश्यक है। पीएम को भेजे मांग–पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि सहायक सचिव कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, शौचालय केयर टेकर एवं प्रधान के मानदेय की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा अलग से करने का वादा मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। रजिस्टर्ड डिप्लोमा होल्डर अथवा जनपद में नियुक्त किसी भी तकनीकी सहायक से स्टीमेट बनवाने की छूट का प्राविधान करने, जिले के प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों की सहभागिता में पंचायतों से जुड़ी

समस्याओं के समाधान के लिए जनपद स्तर पर माह में एक बार उक्त जनपद के जिला अधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में पंचायत दिवस मनाये जाने, जिला योजना समिति में प्रधानों को प्रतिनिधित्व देने का वादा मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त मांगों पर भी सहानुभूति पूर्वक विचार करके प्रदेश में इसे लागू किया जाए। ज्ञापन देते समय ब्लॉक अध्यक्ष राजू सिंह, महामंत्री विमल पत्नी चंद्रजीत यादव, महासचिव राम धीरज साहनी, ग्राम प्रधान पवन कुमार, शिव सहाय, अब्दुल सलाम, परमात्मा प्रसाद, संदीप चौधरी, राम तीरथ, मीरा देवी, जुबैदा खातून, अंजनी देवी आदि लोग उपस्थित रहे।

आधुनिक तकनीकी शिक्षा के लिए स्मार्टफोन व टैब जरूरी - राघवेंद्र प्रताप सिंह

श्रीराम सूर्य मणि महाविद्यालय महुआ खुर्द में 101 छात्र–छात्राओं को वितरित किया गया स्मार्टफोन

अवध की आवाज ब्यूरो

डुमरियागंज (सिद्धार्थ नगर)स श्रीराम सूर्य मणि महाविद्यालय महुआ खुर्द में बृहस्पतिवार को प्रदेश सरकार की यूपी फ्री स्मार्टफोन टैबलेट योजना के अंतर्गत महाविद्यालय में 101 छात्र–छात्राओं को टैबलेट व स्मार्टफोन वितरित किए गए। कार्यक्रम का शुभारभ बतौर मुख्य अतिथि डुमरियागंज के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया ।पूर्व विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि आधुनिक व तकनीकी शिक्षा में स्मार्टफोन व टैब जरूरी हो गया है, छात्र–छात्राएं टैबलेट व स्मार्टफोन के जरिए तकनीकी से जुड़कर अपनी शिक्षा व विभिन्न आयामों व देश दुनिया की तमाम तकनीकी चीजों की जानकारी रह सकती हैं जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके,पूरी उम्मीद करता हूं छात्राएं स्मार्टफोन का सही इस्तेमाल करके अपने आगे की पढ़ाई को सफल बनाएंगे ।कार्यक्रम में प्रबंधक डॉ.कमलेश मिश्र,लवकुश ओझा,नरेंद्र मणि त्रिपाठी व मधुसूदन अग्रहरि ने भी संबोधित किया ।इस दौरान,शत्रुघन सोनी,प्राचार्य डॉ. अजय मिश्रा,ओम प्रकाश मिश्र,बरिष्ठ लिपिक महेश चंद्र चौधरी,नवल पटेल,श्याम गोविन्द पाठक,रन्नो जयसवाल,सुनील शुक्ला,अमित श्रीवास्तव,देवेंद्र प्रताप सिंह,जिला पंचायत सदस्य, प्रदीप कसौधन आदि उपस्थित रहे।

सम्पादकीय

भारतीय लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया में क्रांति की आहट है आरईवीएम

किसी भी राष्ट्र के जीवन में चुनाव सबसे महत्त्वपूर्ण घटना होती है। यह एक यज्ञ होता है। लोकतंत्र प्रणाली का सबसे मजबूत पैर होता है। राष्ट्र के प्रत्येक वयस्क के संविधान प्रदत्त पवित्र मताधिकार प्रयोग का एक दिन। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावों में अधिकतम यानी शत–प्रतिशत मताधिकार का प्रयोग हो, इसके लिये देश में चुनाव प्रक्रिया में एक और क्रांतिकारी कदम की दिशा में अग्रसर होते हुए एक नये अध्याय की शुरुआत होने जा रही है, जिसके अन्तर्गत रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (आरईवीएम) का मॉडल विकसित कर चुनाव आयोग ने महत्त्वपूर्ण पहल की है। चुनावों के दौरान यह मशीन उन घरेलू प्रवासियों के लिए वरदान साबित होगी, जो शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के सिलसिले में अपने चुनाव क्षेत्रों से बाहर रहते हैं।

आरईवीएम को चुनाव प्रक्रिया में शामिल करने के बाद जो प्रवासी जहां है, वहीं से मतदान कर सकेगा। निश्चित ही इसके लागू होने से मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा एवं लोकतंत्र में जनभागीदारी अधिकतम होने लगेगी। चुनाव आयोग के मुताबिक अपने चुनाव क्षेत्रों से बाहर रहने के कारण करीब 30 करोड़ मतदाता मतदान से वंचित रह जाते हैं। शिक्षा या रोजगार की व्यस्तता के कारण उनके लिए अपने क्षेत्र में पहुंचकर मतदान करना सुविधाजनक नहीं होता। आरईवीएम के जरिए ऐसे मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया में शामिल कर मतदान प्रतिशत बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी, जो भारतीय लोकतंत्र को अधिक सशक्त एवं प्रभावी बना सकेगा।

चुनाव आयोग इस नयी प्रक्रिया एवं नये मॉडल का प्रदर्शन 16 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में करेगा, जिसमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित कर उनके सुझाव और आपत्तियों के लिये खुला मंच प्रस्तुत किया जायेगा। इसे हम भारत की चुनाव प्रक्रिया में एक नये सूरज का अवतरण मान सकते हैं, एक अभिनव एवं क्रांतिकारी दिशा में चुनाव के महाकुंभ को अग्रसर करते हुए इसे अधिक सशक्त एवं प्रभावी बना सकेंगे। चुनाव आयोग की इस शुभ–शुरुआत का स्वागत होना चाहिए। जिस तरह 1982 केरल के एक विधानसभा क्षेत्र में पहली बार ईवीएम का प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल करते हुए क्रांति की शुरुआत हुई थी उसी तरह चुनाव प्रक्रिया में आरईवीएम की शुरुआत से चुनाव प्रक्रिया की तस्वीर बदलेगी, मतदाता जहां ज्यादा जागरूक होगा, राजनीतिज्ञ भी ज्यादा समझदारी से चुनाव में हिस्सेदारी करेंगे। हालांकि आरईवीएम को चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए आयोग को अभी अनेक संघर्षों, आलोचनाओं, बाधाओं के साथ कई कानूनी, तकनीकी और राजनीतिक अड़चनों को पार करना है। जिस तरह मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने के प्रस्ताव पर सवाल उठे थे, उसी तरह अब आरईवीएम को लेकर भी विपक्षी दल शंकाएं उठा रहे हैं।

लम्बे समय से चुनाव में गिरता मतदान का प्रतिशत चिन्ता का विषय बना हुआ है। वास्तविक लोकतंत्र वही है जिसमें हर व्यक्ति अपने मतदान का उपयोग करते हुए अपने प्रतिनिधि चुने। लेकिन हर व्यक्ति अपने मत का उपयोग नहीं कर पाता, क्योंकि वह अपने मूल स्थान से दूर दूसरे शहरों या कस्बों में रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, पारिवारिक कारणों से होता है। अगर ऐसे लोगों को मतदान में हिस्सेदारी का अवसर दिया जाता है, तो इससे निस्संदेह मत प्रतिशत बढ़ेगा। मगर दिक्कत यह है कि ऐसे लोगों की पहचान सुनिश्चित करना और वे जहां रह रहे हैं, वहां मतदान केंद्र स्थापित कर पाना कैसे संभव होगा? इस बड़ी बाधा को दूर करना चुनाव आयोग के सम्मुख एक बड़ी चुनौती रही है, वहीं लोकतंत्र में जन प्रतिनिधियों को चुनने में समग्रता एवं बहुसंख्य मतदाताओं के मतों का उपयोग न होना एक अधूरापन है। लोकतंत्र की मजबूती की दृष्टि से यह वाकई चिंताजनक है कि कई चुनाव क्षेत्रों में करीब आधी आबादी की मतदान में सहभागिता नहीं होती।

जनतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू चुनाव है, जनतंत्र में स्वस्थ मूल्यों को बनाये रखने के साथ उसमें सभी मतदाताओं की सहभागिता को सुनिश्चित करना जरूरी है। इसके लिये आरईवीएम के प्रयोग का प्रस्ताव सैद्धांतिक तौर पर एक सराहनीय एवं जागरूक लोकतंत्र की निशानी है। क्योंकि आजादी के बाद से ही जितने भी चुनाव हुए हैं, उनमें लगभग आधे मतदाता अपने मत का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा हर चुनाव में होता आया है। इसलिए लंबे समय से मांग उठती रही थी कि ऐसे लोगों के लिए मतदान का कोई व्यावहारिक एवं तकनीकी उपाय निकाला जाना चाहिए। उसी के मद्देनजर निर्वाचन आयोग के द्वारा घरेलू प्रवासियों के लिए आरईवीएम का प्रस्ताव एक सूझबूझभरा एवं दूरगामी सोच एवं विवेक से जुड़ा उपक्रम है। जरूरत है राजनीतिक दल ऐसे अभिनव उपक्रम का विरोध करने या अवरोध खड़ा करने की बजाय उसका अच्छाइयों को स्वीकार करते हुए स्वागत करें।

हमने देखा है ईवीएम कितनी उपयोग साबित हुई है, फिर इसको लेकर भ्रम बने हुए हैं और हर चुनाव के बाद कुछ आवाजें मतदान में हुई गड़बड़ी को लेकर उठती रहती हैं, उसमें स्वाभाविक ही आरवीएम भी संदेह से परे नहीं होगी। जब मतदाता पहचानपत्र को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रस्ताव आया, तब भी इसी शंका के चलते सवाल उठे थे कि कोई भी बाहरी व्यक्ति मतदान में गड़बड़ी कर सकता है। इसलिए आरवीएम को पूरी तरह भरोसेमंद बनाना होगा। सबसे बड़ा विरोध कांग्रेस की ओर से इसके भरोसेमंद एवं निष्पक्ष होने के लेकर है, जाहिर है, कांग्रेस के साथ–साथ दूसरे दलों की तरफ से भी ऐसे एतराज उठने की संभावना है। मगर यह प्रस्ताव अगर किन्हीं वजहों से व्यावहारिक रूप नहीं ले पाता, तो ऐसे करोड़ों लोगों का मताधिकार फिर अंधेरों में रहेगा। तमाम अपीलों और जागरूकता अभियानों के बावजूद हर चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों में पचास प्रतिशत से भी कम मतदान हो पाता है। इस तरह जन प्रतिनिधित्व का मकसद ही अधूरा हो जाता है। इसे दूर करना जितना निर्वाचन आयोग का नैतिक और संवैधानिक दायित्व है, उतना ही राजनीतिक दलों को भी इसे सुनिश्चित करने में अपनी सकारात्मक पहल करनी चाहिए।

सबसे प्रमुख सवाल कि मतदाता कैसे स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का उपयोग करे। मगर जैसा कि निर्वाचन आयोग का दावा है, उससे लगता है कि उसने तमाम आशंकाओं, पक्षों एवं आलोचनाओं पर गंभीरता से विचार कर लिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने इसे शानदार पहल बताते हुए कहा कि यह अच्छी बात है कि आयोग यह सब लोकतांत्रिक तरीके से कर रहा है। लोकतंत्र का हित इसी में है कि घरेलू प्रवासियों के मतदान से दूर रहने की समस्या के समाधान के लिए नकारात्मक की बजाय सकारात्मक रवैया अपनाया जाए। आयोग का यह भी कहना है कि इस मशीन को त्रुटिहीन बनाया जाएगा। कई चुनाव विशेषज्ञ इसे एक क्रांतिकारी पहल मान रहे हैं। भारत की इस बड़ी पहल से दुनिया की चुनाव प्रक्रिया को एक नई रोशनी मिलेगी। इससे भारत का लोकतंत्र अधिक सशक्त, निष्पक्ष एवं प्रभावी बनकर प्रस्तुत होगा। जन प्रतिनिधित्व एवं सत्ता तक पहुँचने के रास्तों को अधिक कारगर, निष्पक्ष एवं बहुसंख्य मताधिकार पूर्ण बनाने में सहयोग मिलेगा। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (आरईवीएम) के लिये चुनाव आयोग की प्रभावी भूमिका प्रशंसनीय है। उसकी सतत जागरूकता एवं चुनाव सुधार की प्रक्रिया निरन्तर जारी रहनी अपेक्षित है, इसी से शत–प्रतिशत मतदान के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा।

ऑनलाइन गेमिंग पर नकेल

आदित्य नारायण

चाइनीज ऐप और मोबाइल गेम के बाद अब केन्द्र सरकार ने जुआ या स्किल वाले ऑनलाइन गेमिंग पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों से सवाल उठते रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग ने युवा और बच्चों के जीवन को काफी हद तक प्रभावित किया है। कोरोना महामारी के दौरान लम्बे चले लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन गेमिंग ऐप तेजी से लोकप्रिय हुए। तब घरों में बंद लोगों ने ऑनलाइन गेमिंग के सहारे अपना समय बिताया, लेकिन इनके साथ ही समाज में विकृतियां भी उभरने लगीं। लोग इसकी लत का शिकार होते रहे। फिर कुछ ऐसी ऐप भी आ गई जो खुलेआम जुआ और सट्टा खेलने को प्रोत्साहित करती थी। स्किल के नाम पर सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा दिया गया। फिर मोबाइल लोन ऐप सामने आए और उन्होंने झटपट तुरन्त लोन देने के नाम पर युवाओं के साथ–साथ कारोबारियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। ऐसी खबरें लगातार आती रही हैं कि किशोर और युवा अभिभावकों से छुपकर गेम्स खेलते हैं या लोन लेते हैं, फिर उन्हें लूटा जाता है। कई युवा अपने अभिभावकों को लाखों का चूना लगा चुके हैं। मोबाइल प्ले स्टोर पर अनगिनत ऐप आ गए जो आपको सस्ते में लोन देने का दावा करते हैं। लोग फंसते गए और उन्हें पता ही नहीं था कि इस फ्रॉड से बाहर कैसे निकलें।

वित्त विशेषज्ञों ने भी इन ऐप्स को बच्चों, युवाओं को भ्रमित कर ठगी करने वाला करार दिया था। ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर अंकुश लगाने के लिए एक नियामक तंत्र स्थापित करने की जमकर वकालत की गई थी। इसके बाद से ही इलैक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने काम करना शुरू कर दिया था। मंत्रालय ने अब ऑनलाइन गेमिंग कम्पनियों के लिए नियमों का मसौदा जारी कर दिया है। इस मसौदे में ऑनलाइन गेमिंग कम्पनियों के लिए भारत में लागू कानूनों का अनुपालन जरूरी कर दिया गया है। अब सट्टेबाजी से संबंधित कानून इन कम्पनियों पर लागू होंगे। इन कम्पनियों को स्व–नियामकीय निकाय के साथ पंजीकृत करने, इनके भारतीय पतों और गेम खेलने वालों के सत्यापन को अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों को जिम्मेदार ढंग से संचालित करना है। ऑनलाइन कम्पनियां कोघ्खेल में शामिल लोगों की जमा राशि की निकासी या घरिफंड, जीती हुई रकम के विवरण, फीस और अन्य शुल्कों के बारे में बताना होगा। स्व–नियामकीय निकाय कम्पनियों और खेलने वाले लोगों के बीच शिकायतों का निपटारा भी करेगा। स्किल और जुआ संबंधी सभी तरह के गेम जिनमें पैसा शामिल होता है, सरकार के रेगुलेशन के दायरे में होंगे। जिन गेम्स से धन कमाया जाता है उन पर सरकार की नजर रहेगी।

इसी साल अगस्त में नियमन का मसौदा तैयार करने वाले एक भारतीय पैनल ने यह तय करने के लिए एक नए नि काय का प्रस्ताव रखा था कि क्या गेम में स्किल या अवसर शामिल हैं, और फिर स्किल गेम्स को नियोजित संघीय नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। शिकायत निवारण तंत्र द्वारा एक समिति बनाने के लिए कहा गया था, जो यह तय करे कि स्किल गेमों के लिए रजिस्ट्रेशन हो और जुआ आधारित गेम राज्य सरकार की निगरानी में नियंत्रित किए जाने का उल्लेख किया गया था। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार 26 अक्तूबर की एक सरकारी बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस तरह के भेदभाव पर आपत्ति जताई और सभी प्रकार के खेलों पर विस्तारित निरीक्षण की मांग की। प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना था कि कानूनी स्पष्टता की कमी और अदालती फैसलों के विपरीत होने के कारण गेमिंग को स्किल या अवसर के रूप में अलग करना आसान नहीं था। अधिकारी का कहना था कि ऑनलाइन गेमिंग को बिना किसी भेद के एक गतिविधि, सेवा के रूप में माना जा सकता है और हर तरह के गेम पर नजर रखनी चाहिए। भारत में ऑनलाइन गेम्स को परिभाषित करना विवादास्पद रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ताश के गेम और कुछ फैंटेसी गेम कौशल आधारित हैं और कानूनी हैं जबकि विभिन्न राज्यों की अदालतों ने इन खेलों के बारे में अलग–अलग विचार रखे। भारत में गेमिंग सैक्टर तेजी से बढ़घ्रहा है। एक अनुमान के अनुसार 2026 तक भारत में गेमिंग सैक्टर सात बिलियन डॉलर के लगभग हो जाएगा और इसमें रियल मनी गेम का प्रभुत्व अधिक होगा। ऑनलाइन गेमिंग सैक्टर को भारत में पिछले दिनों से काफी रफ्तार मिली है। इसे देखते हुए इनका विनियमन जरूरी समझा जाने लगा था। जिन गेम्स में धन लिप्त है उनके व्यापार पर निगरानी रखी ही जानी चाहिए। सरकार तो अपना काम कर रही है लेकिन अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों और युवाओं की आदतों और व्यवहार पर नजर रखें, ताकि वो इनकी लत का शिकार न हो जाएं। ऑनलाइन गेम्स के जोखिमों के बारे में अभिभावकों को पता होना ही चाहिए।

नए साल पर शर्मसार दिल्ली

देश की राजधानी दिल्ली के लिए नए साल की शुरुआत एक शर्मनाक, खौफनाक घटना के साथ शुरु हुई। 31 दिसम्बर और एक जनवरी की दरम्यानी रात 20 बरस की अंजलि सिंह नाम की लड़की अपनी सहेली के साथ स्कूटी से लौट रही थी। सुल्तानपुरी के कृष्णविहार इलाके में स्कूटी को एक कार ने टक्कर मारी, इसके बाद अंजलि कार के नीचे आ गई और लगभग 12 किमी तक कार के साथ घिसटती गई। इस हादसे में उसकी जान चली गई। अंजलि का शव दिल्ली के जौंती गांव इलाके में निर्वस्त्र मिला। जिसके बाद आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं कि फिर से निर्भया कांड जैसी कोई भयावह घटना न हुई हो। लड़की की मां ने भी यह डर व्यक्त किया कि उनकी बेटी के साथ हादसे से पहले कोई यौन शोषण तो नहीं हुआ, क्योंकि उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। हालांकि पुलिस पहले से ही इस बात से इंकार कर रही थी कि बलात्कार नहीं हुआ है और गाड़ी में शरीर के फंसने, सड़क पर घिसटने के कारण कपड़े फट गए होंगे। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बलात्कार जैसी किसी बात से इंकार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अंजलि के शरीर पर जितने भी जख्म हैं, वो तेज झटका लगने और गाड़ी से घिसटने के कारण हैं। चोट लगने और अत्यधिक खून बहने की वजह से अंजलि ने दम तोड़ दिया। अंजलि के मामा ने भी कहा कि परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा है। गनीमत है कि अंजलि यौन हिंसा का शिकार नहीं हुई। हालांकि जिन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई, वह इतनी त्रासद हैं कि उसके बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में कुर्सी या मेज की जरा सी ठोकर भी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन अंजलि तो 12 किमी तक सड़क पर कार के साथ घिसटती रही। उसके हिस्से ऐसी दर्दनाक मौत आई, क्योंकि समाज का एक तबका पूरी तरह संवेदनाओं से शून्य है, इसमें पुलिस प्रशासन भी आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बाद में आई, लेकिन पुलिस ने पहले ही बता दिया था कि गाड़ी के साथ घिसटने के कारण कपड़े फट गए और बलात्कार नहीं हुआ है। क्या दिल्ली पुलिस में यह विशेषज्ञता भी है कि वह 12 किमी तक घिसटे हुए शरीर को देखकर बता दे कि मरने से पहले उसके साथ क्या हुआ था, क्या नहीं। पुलिस के दावे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साम्यता है और पीड़ित परिवार ने भी इसे स्वीकार कर लिया है, तो फिर बलात्कार वाले कोण से जांच अब नहीं होगी। वैसे यह जानकारी भी सामने आई है कि 20 बरस की मृतका अपने परिवार में इकलौती कमाऊ सदस्य थी, उसके पिता की कुछ साल पहले मृत्यु हो गई थी। अंजलि की मां का कहना है कि हमारे पास 10 रुपए भी अंतिम संस्कार के नहीं हैं। अंजलि शादी या अन्य समारोहों में मेहमानों के स्वागत का काम किया करती थी और रोजाना लगभग 5 सौ रुपए कमाती थी, जिससे घर चलता था। हादसे की रात भी वह बाहर थी और रात साढ़े आठ बजे उसने अपनी मां को फोन पर कहा था कि उसे देर हो जाएगी। इसके बाद सीधे सुबह उन्हें अपनी बेटी की मौत की खबर मिली। अंजलि के घर के हालात देखकर समझा जा सकता है कि अपनी आशंकाएं व्यक्त करने की शक्ति शायद उनमें न हो और उन्होंने वही बात स्वीकार कर ली हो, जो रिपोर्ट में सामने आई है। जो पांच आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, उन पर अब केवल सड़क दुर्घटना वाले कोण से जांच बिठाई जाएगी और संभवतरू सजा भी इसी मुताबिक हो। हालांकि उनका दोष कब और कैसे सिद्ध हो पाएगा, अभी यही नहीं कहा जा सकता, सजा तो उसके बाद की बात है। फिलहाल इस मामले ने राजनैतिक मोड़ भी ले लिया है, क्योंकि आरोपियों में से एक मनोज मित्तल का संबंध भाजपा से बताया जा रहा है। सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी में भाजपा के स्वागत वाले पोस्टर्स में मनोज का चेहरा भी है। दिल्ली पर सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी ने इस मामले में भाजपा पर उंगली उठानी शुरु कर दी। जिसके बाद गृहमंत्री अमित शाह ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। राजनैतिक तौर पर मामला भाजपा के खिलाफ जाता और बात आगे बढ़ती, इससे पहले ही गृहमंत्रालय ने जांच का आदेश दे दिया है। जिससे कम से कम विरोधियों को उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये सवाल तो उठेगा ही कि आखिर ऐसी किसी भी जांच की नौबत क्यों आई। 31 दिसंबर का वक्त अतिरिक्त सावधानी बरतने का होता है, क्या यह बात दिल्ली पुलिस नहीं जानती है। कोई तेज रफ्तार गाड़ी किसी को ठोकर मार कर भाग जाए या कोई नशे में धुत्त सवार गाड़ी पलटा दे, यह ऐसा मामला नहीं है। इस घटना में एक इंसानी शरीर को सौ–पांच सौ मीटर नहीं, पूरे 12 किमी तक कार के साथ घसीटा गया। खबरें हैं कि एक सामान पहुंचाने वाले लड़के ने और एक दूध वाले ने कार के साथ लड़की को घिसटते देखा और इसकी इत्तिला पुलिस को की, लेकिन पुलिस फिर भी सुस्त बनी रही। पुलिस को पता होना चाहिए कि नए साल के जश्न में किस तरह असामाजिक तत्व नशा करके वाहन चलाने या हुड़दंग मचाने सड़कों पर निकलते हैं। फिर उसके पास कोई शिकायत आई, तो उसने फौरन कार्रवाई क्यों नहीं की। 12 किमी के उस दायरे में पुलिस का गश्ती वाहन क्यों नहीं था। कायदे से तो राजधानी को ऐसे संवेदनशील मौके पर सुरक्षित रखने के लिए चप्पे–चप्पे पर पुलिस का पहरा होना चाहिए। अगर कड़ा पहरा होता तो शायद दुर्घटना होते ही अंजलि को मदद मिल जाती और उसकी जान बच जाती। अभी कुछ महीने पहले दिल्ली की सड़कों पर निगरानी के लिए 56 हजार सीसीटीवी लगाने की योजना केजरीवाल सरकार ने बनाई थी। क्या ये कैमरे ऐसे हादसों को रिकार्ड करने का ही काम करेंगे या फिर इनसे बचाव का भी कोई इंतजाम होगा। आखिर में एक सवाल समाज से, कि किस तरह की परवरिश हम अपने लड़कों की कर रहे हैं, जो नशा करने, लड़कियों के साथ बदसलूकी करने और अपने गलत काम पर शेखी बघारने से बाज नहीं आते। जिन लड़कों ने रफ्तार का मजा लेने के लिए एक लड़की को अपनी कार के नीचे घसीटा, क्या वे हाड़–मांस के इंसान नहीं थे, जो इस तरह संवेदनहीन हो गए। क्या मृतका की चीखें उन्हें सुनाई नहीं दी थीं। क्या समाज इन चीखों को सुनकर कोई सबक लेगा।

युद्ध से हासिल हुई बर्बादी, रूस जीतकर भी हारा, यूक्रेन बर्बाद हुआ बेचारा

संजीव ठाकुर

युद्ध और हिंसा क्रोध से शुरू होकर पश्चाताप और दुखों के चिंतन में खत्म होता है। रूस और यूक्रेन युद्ध कि कइ दिनों से ज्यादा के युद्ध की परिणति में शिवाय पश्चाताप के कुछ नहीं हैस रूस अपने सनकी राष्ट्रपति पुतिन की जिद की बलि चढ़ गया है। वह यूक्रेन से जीत कर भी मानसिक और वैचारिक रूप से हार गया है, रूस अपने को जितना बलशाली, शक्तिशाली समझता था अब उसकी पोल खुल गई है,अनेकों माह से ज्यादा के युद्ध में रूस यूक्रेन जैसे छोटे देश को जीत नहीं पाया हैस यूक्रेन भी अपनी राष्ट्रपति की हठधर्मिता के कारण पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका है. यूक्रेन के 1करोड़ 40 लाख नागरिक देश छोड़कर शरणार्थी बन चुके हैं। 40 हजार इमारतें बर्बाद हुई 20 लाख बच्चे घरों से दूर होकर शिक्षा से वंचित हो गए। ईसी तरह यूक्रेन तथा रूस के लगभग 50 बाजार सैनिक युद्ध में मारे गए है। यह युद्ध की विभीषिका कहां तक जाएगी इसका आकलन करना तो कठिन है पर इसके परिणाम अत्यंत अमानवीय,कारुणिक और आर्थिक नुकसान देने वाले साबित हुए हैं। रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन के तथाकथित दोस्तों अमेरिका तथा नैटो देशों ने सक्रियता से मैदान में साथ नहीं दिया, केवल दूर से यूक्रेन को शाबाशी देते रहे यूक्रेन अब संपूर्ण बर्बादी के कगार पर है। रूस का उसके अपने ही राष्ट्र में युद्ध के खिलाफ विरोध के स्वर उभर रहे हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त पत्रकार ने अपने पूर्व में प्राप्त नोबेल पुरस्कार मेडल को बेचने का ऐलान किया है एवं यूक्रेन में मरने वाले हजारों बच्चों के हित में वह धनराशि रेड क्रॉस को प्रदान करेगा। पत्रकार ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का रूस की जनता अंदरूनी तौर पर विरोध करती है एवं भारी असंतोष भी है, मैं आपको रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि का इतिहास बताता हूं। यूक्रेन एक छोटा सा राज्य है, उसकी सैन्य शक्ति भी इतनी क्षमतावान नहीं है कि रूस या अन्य शक्तिशाली देश का सैन्य मुकाबला कर सके,पर अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के 30 देशों के बहकावे में आकर उसने रूस को नाराज करना शुरू कर दिया था। यूक्रेन को यकीन था कि रूस के आक्रमण के समय अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजरायल और नाटो के कई देश उसकी रक्षा करेंगे, पर ताकतवर,शक्तिमान रूस के हमले के सामने ना तो अमेरिका ने अपना सैन्य आक्रमण किया ना ब्रिटेन ने अपनी सेना ही भेजी और ना ही अन्य नाटो देश में रूस के खिलाफ किसी तरह की जंग ही की है ,केवल दूर से बैठकर समझौते करने की बात करते रहे और रूस के आक्रमण की निंदा ही की है। यह आलेख लिखते तक रूस ने कीव पर कब्जा भी कर लिया होगा और उसके समस्त एयर बेस सैनिक अड्डों को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन का एयर डिफेंस पूरी तरह चरमरा गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बताया कि रूस ने सभी सैनिक हवाई अड्डों पर रॉकेट लॉन्चर दाग कर उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया है, यूक्रेन के लगभग 40 सैनिकों को मार भी गिराया है, इसमें 10 निर्दोष नागरिक भी मारे गए हैं। रूस ने दावा किया था कि वह नागरिक ठिकानों पर बमबारी नहीं करेंगा पर मिसाइल तथा गोलियां सैनिकों तथा नागरिकों को अलग–अलग नहीं पहचानती है, और यही वजह है कि सैनिकों के साथ नागरिक भी मारे गए। वर्ष 1914 में यूक्रेन से रूस ने क्रीमिया को अलग कर अपने अधिपत्य में ले लिया था। रूस का कहना है कि अमेरिका ब्रिटेन और नाटो देश यूक्रेन को एक न्यू क्लियर सामरिक अड्डा रूस के खिलाफ बनाने की तैयारी कर चुके हैं, और इन सभी देशों के साथ यूक्रेन भी रूस की प्रतिरक्षा प्रणाली को बहुत बड़ा खतरा बन गया है। यूक्रेन पर अमेरिकी प्रशासन का पूरा पूरा नियंत्रण है, यूक्रेन प्रशासन केवल कठपुतली मात्र है। इसे संचालित करने वाला अमेरिका तथा ब्रिटेन ही है। यूक्रेन लगातार नाटो देश की सदस्यता के लिए प्रयास करता रहा है और अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन नाटो देश का सदस्य बन कर रूस के खिलाफ एक सामरिक अड्डे की तरह उनके काम आए। तत्कालिक कारणों में रूप द्वारा गैस तथा तेल के लिए बिछाई गई पाइप लाइन जो जर्मन तक गैस तथा तेल पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ थी। जर्मन एक बहुत बड़ा तेल तथा गैस का बाजार है, यहां से सारे यूरोप में आर्थिक गतिविधि शुरू होकर गैस तथा तेल की सप्लाई की जाती है जो कि एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र है। यह गैस पाइपलाइन यूक्रेन के क्षेत्र से होकर जनवरी तक जाती है। इससे नाटो देश को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान की संभावना भी है। दूसरी तरफ यूक्रेन, क्रीमिया को अपने पास वापस अपने अधिपत्य में लेना चाहता है, जो वर्तमान में रूस के कब्जे में है, इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के दो बड़े क्षेत्र लुहानस्क और डोनट्स रिपब्लिक को राज्य के रूप में मान्यता दे दी है, यह बहुत बड़े क्षेत्र और इन्हीं के माध्यम से उसने अपनी सेना को यूक्रेन में दाखिल भी किया था। इन दो बड़े रिपब्लिक को देश की तरह मान्यता देने पर अमेरिका तथा ब्रिटेन और नाटो देशों ने अंतरराष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन की बात कह कर भरपूर सार्वजनिक निंदा भी की है और किसी स्वतंत्र देश की प्रभुसत्ता पर हस्तक्षेप भी बताया है। रूस के इस यूक्रेन पर आक्रमण से भारत की चिंता अपने 20 हजार नौजवान छात्रों को जो युक्रेन में अध्ययन कर रहे थे। अब वहां फंसे हुए हैं, उन्हें बचाने की भी है। यूक्रेन तथा रूस के बीच शांति स्थापना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मध्य रात्रि के बीच लगभग 40 मिनट बात कर शांति स्थापना के अपील भी की है एवं नागरिकों को वहां से निकालने की चिंता से भी अवगत कराया है। निश्चित तौर पर भारत के यूक्रेन तथा रूस के साथ अच्छे संबंधों के कारण शांति बहाली की अपील कर रहा है, और इसका असर भी हो सकता है । यह तो तय है कि रूस और यूक्रेन के बीच यदि युद्ध में कोई भी विदेशी ताकत हस्तक्षेप करती है, तो विश्व युद्ध की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। रूस ने यूक्रेन की मदद के लिए किसी भी देश के आने पर भयानक परिणाम होने की चेतावनी भी दे डाली है। यूक्रेन को इस आफत में फंसाने एवं उसे रूस के विरुद्ध उकसाने के लिए अमेरिका ब्रिटेन और नाटो देशों की भूमिका सदैव संदिग्ध ही रही है।

हल्द्वानी प्रोटेस्ट के स्वरूप ने साबित किया– शाहीन बाग संयोग नहीं प्रयोग था जोकि दोहराया जा रहा है

अवैध कॉलोनियों से जब भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है तो उसे सियासी लोग धार्मिक रंग देने का काम करते हैं। दिल्ली में पिछले साल एमसीडी का बुलडोजर शाहीन बाग समेत कई अन्य इलाकों में पहुँचा तो इस कार्रवाई को एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ अभियान करार दिया गया। अब उत्तराखंड चर्चा में है क्योंकि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की जमीन पर बनी अवैध कॉलोनी से कब्जा हटाने का जो आदेश उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दिया है उसके खिलाफ सियासत शुरू हो गयी है। एकदम शाहीन बाग के आंदोलन की तर्ज पर महिलाओं और बच्चों को ठंड के मौसम में आगे कर प्रदर्शन करवाया जा रहा है, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। यहाँ हमें समझना होगा कि सरकारी जमीन सार्वजनिक संपत्ति होती है किसी एक की बपौती नहीं। सरकारी जमीन से कब्जा छुड़वाने के प्रयास को अन्याय का रूप देना गलत है। देश संविधान से चलता है ना कि भावनात्मक या धार्मिक आधार पर। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है तो नेताओं को बड़बोले बयान देने की बजाय अदालत के आदेश का इंतजार करना चाहिए। वैसे हल्द्वानी में आंदोलन का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है उससे एक बात साबित हो गयी है कि शाहीन बाग कोई संयोग नहीं बल्कि प्रयोग था जोकि अब जगह–जगह दोहराया जा रहा है।

जहां तक हल्द्वानी मामले की बात है तो आपको बता दें कि अवैध कॉलोनी बताये जा रहे बनभूलपुरा के पांच हजार से ज्यादा घरों पर संकट मंडराने लगा है क्योंकि रेलवे ने अपनी जमीन पर कब्जा छुड़ाने के लिए जो याचिका दायर की थी उस पर सुनवाई के बाद उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जमीन खाली कराने के निर्देश दिये हैं। इसके बाद सियासत ऐसी शुरू हो गयी है कि इस पहाड़ी राज्य के नेताओं से लेकर हैदराबाद के ओवैसी तक इस मामले में कूद गये हैं। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुँच चुका है और पांच जनवरी को इस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका स्थानीय निवासियों के साथ हल्द्वानी के कांग्रेस विधायक ने दाखिल की है। उनके वकील सलमान खुर्शीद हैं। दूसरी याचिका वकील प्रशांत भूषण ने दाखिल की है। रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा सुनवाई करेंगे।

हम आपको बता दें कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर को हल्द्वानी में बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए ढांचों को गिराने के आदेश दिए थे। न्यायालय ने कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए पैरा मिलिट्री फोर्स की मदद ले, फिर भी कोई दिक्कत हो तो बलपूर्वक कार्रवाई की जाए। इसके बाद जगह खाली करने के लिए स्थानीय समाचार पत्रों की मदद से नोटिस दिये गये। जिसके बाद हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में क्षेत्र के निवासियों ने उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। इलाके के लोगों का कहना है कि वे लोग इस क्षेत्र में 70 साल से रह रहे हैं। वहां 20 मस्जिदें, 9 मंदिर, पानी की टंकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1970 में डाली गई एक सीवर लाइन, दो इंटर कॉलेज और एक प्राथमिक विद्यालय है इसलिए यह क्षेत्र अवैध कब्जे वाला नहीं है। इलाके के लोगों का कहना है कि हम प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि वे इस तथा–कथित अतिक्रमण को हटाने पर मानवीय पहलू से विचार करें। इलाके के लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर यह रेलवे की जमीन थी तो सरकार ने इसे पट्टे पर कैसे दिया था?

इस मामले में क्षेत्र के कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा, श्करीब सौ साल से इस क्षेत्र में लोग बसे हुए हैं। यहां 70 साल पुरानी मस्जिदें और मंदिर हैं। यहां नजूल जमीन, पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और लीजधारक हैं।श उन्होंने कहा, श्रेलवे जिस 78 एकड़ जमीन को अपना बताता है, उसे खाली करने का विरोध करने के लिए हम व्यक्तिगत रूप से उच्च न्यायालय गये। हम उच्चतम न्यायालय भी गये जहां हमारे वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद मामले की पैरवी कर रहे हैं लेकिन जिस सरकार ने जमीन पर स्कूल एवं अस्पताल बनवाये, उसने अपने नागरिकों की कोई परवाह नहीं की।'' विधानसभा में हल्द्वानी सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे सुमित हृदयेश ने हाल में प्रदर्शनकारियों के धरने में भी हिस्सा लिया था। हम आपको बता दें कि यह सीट पारंपरिक रूप से वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं उनकी मां इंदिरा हृदयेश जीतती थीं।

जहां तक इस पूरे मामले का सवाल है तो आपको बता दें कि उत्तराखंड उच्च न्यायायल ने हल्द्वानी के इस इलाके में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का 20 दिसंबर को आदेश दिया था। न्यायालय ने अतिक्रमणकर्ताओं को वह जगह खाली करने के लिए एक हफ्ते का नोटिस देने का आदेश दिया था। हालांकि बनफूलपुरा के हजारों बाशिंदों ने अतिक्रमण हटाने का यह कहते हुए विरोध किया कि वे बेघर हो जायेंगे और स्कूल जाने वाले उनके बच्चों का भविष्य तबाह हो जाएगा।

इस बीच, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी अनुरोध किया है कि वे अतिक्रमण हटाने संबंधी इस आदेश पर मानवीय तरीके से विचार करें क्योंकि ऐसा होने पर हजारों लोग बेघर हो जाएंगे। उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम एक खुला पत्र लिखते हुए इसे सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि कानूनी पक्ष के इतर मानवीय दृष्टिकोण से मामले में कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। हरीश रावत ने अपने पत्र के माध्यम से सवाल भी किया है कि यदि 50 हजार से ज्यादा लोगों को हटाया जाएगा तो ये लोग कहां जाएंगे? हरीश रावत ने कहा है कि अशांति का वातावरण पूरे हल्द्वानी और कुमाऊं के अंचल में फैलेगा जोकि ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आज भले कुछ लोग चुप हों लेकिन जब स्थितियां बिगड़ेंगी तो वो लोग भी सरकार के विवेक पर उंगली उठाएंगे। हरीश रावत ने पत्र के माध्यम से चेतावनी भी देते हुए कहा है कि जहां तक सवाल हमारे कर्तव्य का है, तो हम केवल इतना भर कर सकते हैं कि जब घर तोड़ने के लिए हथौड़ा उठेगा तो हम उसके आगे बैठ सकते हैं।

वहीं एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री को इंसानियत की बुनियाद पर हल्द्वानी के लोगों की मदद करनी चाहिये और उन्हें वहां से नहीं निकालना चाहिए। उन्होंने सवाल किया है कि हल्द्वानी के लोगों के सर से छत छीन लेना कौन–सी इंसानियत है?

बहरहाल, मामला अब न्यायालय में है इसलिए प्रदर्शनकारियों को भी घरों में बैठना चाहिए और नेताओं को भी जुबान पर काबू रखना चाहिए साथ ही सोशल मीडिया पर तनाव बढ़ाने जैसी पोस्ट करने से भी बचना चाहिए। सांप्रदायिक सौहार्द्र कायम रख कर ही हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं।

–नीरज कुमार दुबे

प्रभारी चौकी मझगई विनोद सिंह ने पेश की मानवता की मिशाल

अपने अच्छें कार्यों के चलते जहां रहे वहां के लोगों के दिलों में करते आ रहे राज

पलियाकलां—खीरी। क्या खूब किसी ने लिखा हैं,कि आंखें सिर्फ ष्प्रेमष की भाषा समझती हैं,मिले तो भी छलकती हैं न मिले तो भी छलकती हैं। उक्त पंक्तियां बखूबी मझगई चौकी प्रभारी विनोद सिंह पर सटीक बैठती हुई दिखाई पड़ी।हांड़ कंपाने वाली भीषण ठंड में जब चौकी प्रभारी अपने पुलिस बल के साथ पैदल मार्च करने क़स्बें में निकले तो एक पेड़ के नीचे चौदह वर्ष का भटका हुआ बालक कांपते हुए दिखाई पड़ा तथा शरीर पर बनियान,हाफ अंडरवियर व नंगें पाव भीषण ठंड के मारे कांप रहा पूरा शरीर देख बालक के पास पहुंचे ही बालक रो पड़ा और चौंकी प्रभारी के सीने चिपक गया।चौकी प्रभारी उस बालक को अपने साथ मझगई पुलिस चौकी पर लाकर बालक को गर्म कपड़े,जूता,मौजे पहनाकर भोजन,चाय नाश्ता आदि से बालक की सेवा की फिर बालक से उसका नाम पता जानने लगे पर बालक मूंक बाधिर होने के कारण कुछ भी नहीं बता पाया पर इशारों में सब बता रहा था। जिसकी खोजबीन करने के उपरांत उसका नाम मो०शाकिब पुत्र जमील अहमद निवासी बरवन्डा पलिया के रुप में पहचान हुई।जिसकी सूचना चाइल्ड लाइन पलिया के समन्वयक लवकुश वर्मा व इंद्र कुमार अवस्थी आदि को सूचना देने के साथ ही पता लगे बालक के परिजनों को सूचना दी गयी।बालक की मां रहमतुल जब मझगई चौकी पहुंची तो अपने बालक को देख आंखों में आंसू आ गये।चौकी प्रभारी विनोद सिंह को रहमतुल रोते हुए उनको आशीर्वाद देते हुए आभार जताया।बालक को अपनी मां को सुपुर्द किया गया।वहीं चौकी प्रभारी विनोद सिंह ने बालक के मां के छलकते हुए आंसू को पोछते हुए बालक पर नजर रखने की बात कही।चौकी प्रभारी की इस दरियादिली को देख पूरे क्षेत्रवासी समस्त पुलिस स्टाप की प्रशंशा किये।

बसपा नेता की हत्या के आरोप में हिरासत में लिए गए युवक की संदिग्ध हालात में मौत

सीतापुर। सीतापुर जिले के पिसावां में बसपा के सेक्टर अध्यक्ष की हत्या में नामजद शख्स की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजन पुलिस की पिटाई से मौत की बात कह रहे हैं, वहीं पुलिस का दावा है कि थाने ले जाते समय रास्ते में ही उसकी हालत बिगड़ गई थी और जिला अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। इटावा थाना क्षेत्र के जिगनिया निवासी राम लोटन (58) बसपा के सेक्टर अध्यक्ष थे। मंगलवार रात उसका शव गांव के चकमार्ग पर पड़ा मिला था। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को तहरीर के आधार पर हिरासत में लिया था। इनमें से ही एक राजू (45) निवासी जिगनिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि थाने में पिटाई से राजू की मौत हुई है जबकि अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी एनपी सिंह का कहना है कि राजू को पुलिस हिरासत में थाने ले जाया जा रहा था। रास्ते में ही उसकी हालत बिगड़ गई। इस पर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिसावां ले जाया गया, जहां से चिकित्सक ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में चिकित्सक ने राजू को मृत घोषित कर दिया। शव को मॉर्चरी में रखवा दिया गया है।

दिल्ली का उपहार कांड न बन जाए लेवाना सुइट्स अग्निकांड, 120 दिन में 19 दोषियों को सिर्फ चार्जशीट दी

लखनऊ। होटल लेवाना सुइट्स अग्निकांड के 120 दिन पूरे हो गए। हजरतगंज के इस होटल में बीते साल पांच सितंबर को लगी आग में चार लोगों की मौत हो गई थी। मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब, पुलिस आयुक्त एसबी शिरडकर की संयुक्त जांच में घटना के लिए 19 लोगों को दोषी पाया गया। एक्सईएन ओम प्रकाश मिश्रा, एई राकेश मोहन, जेई जितेंद्र नाथ दुबे, रवींद्र कुमार श्रीवास्तव, गणेशी दत्त सिंह, जयवीर सिंह, मेट राम प्रताप एवं आबकारी विभाग के पूर्व जिला आबकारी अधिकारी संतोष कुमार तिवारी, पूर्व आबकारी निरीक्षक अमित कुमार श्रीवास्तव एवं उप आबकारी आयुक्त जैनेंद्र उपाध्याय। हजरतगंज अखिलेश मिश्रा के मुताबिक दोषी पाए गए एलडीए के इंजीनियरों, अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ जांच जारी है। कई इंजीनियर रिटायर हो चुके हैं। इनमें से कुछ के बयान बाकी है। सभी को नोटिस जारी होगा। जल्द विवेचना पूरी कर सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। मामले में गिरफ्तार होटल मालिक राहुल अग्रवाल, रोहित अग्रवाल व महाप्रबंधक सागर श्रीवास्तव को चार दिसंबर को कोर्ट ने जमानत दे दी थी। वहीं, होटल के तीसरे मालिक बुजुर्ग और बीमार पवन अग्रवाल को कोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत मिल गई है।

हालांकि, इन 120 दिनों में सिर्फ दोषियों को चार्जशीट ही दी जा सकी है। जांच की रफ्तार को देखते हुए आशंका है कि यह दिल्ली का उपहार कांड न बन जाए। अग्निकांड के दोषियों को तीन से चार दिन पहले ही चार्जशीट दी गई है। घटना के चार माह बाद जांच अधिकारी आरोप ही तय कर सके हैं। शासन स्तर पर चार्जशीट देने के लिए अलग—अलग सुनवाई चल रही है। जांच की गति यही रही तो जान गंवाने वाले चार बेगुनाहों को इंसाफ कब मिलेगा, यह बड़ा सवाल है।

जांच में ये मिले थे दोषी

गृह विभाग के पूर्व अग्निशमन अधिकारी सुशील यादव, सेवानिवृत्त मुख्य अग्निशमन अधिकारी अभयभान पांडेय, अग्निशमन अधिकारी योगेंद्र प्रसाद, मुख्य अग्निशमन अधिकारी विजय कुमार सिंह, ऊर्जा विभाग के सहायक निदेशक विजय कुमार राव, जेई (एई) आशीष कुमार मिश्रा, एसडीओ (एक्सईएन) राजेश कुमार मिश्रा, नियुक्ति विभाग के पीसीएस एवं पूर्व विहित अधिकारी एलडीए जोन छह महेंद्र कुमार मिश्र, एलडीए के पूर्व एक्सईएन अरुण कुमार सिंह,

चार माह में किसने क्या किया

एलडीए : मानचित्र निरस्त कर होटल ध्वस्त करने का दिया नोटिस

अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद होटल लेवाना सुइट्स का स्वीकृत मानचित्र निरस्त कर इसे ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया गया। जांच में दोषी पाए गए मानचित्र सेल के इंजीनियरों पर भी कार्रवाई के लिए शासन को विवरण भेजा है। दोषी पाए गए प्राधिकरण के अफसर, इंजीनियर और कर्मचारियों को चार्जशीट दी गई। हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, नहीं तो अब तक होटल पर बुलडोजर चल चुका होता।

पुलिस विभाग : होटल मालिकों, महाप्रबंधक के खिलाफ आरोप पत्र

हादसे के बाद हजरतगंज के एसएसआई दयाशंकर द्विवेदी ने तीन होटल मालिकों व महाप्रबंधक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, लापरवाही सहित कई संगीन धाराओं में केस दर्ज कराया। विवेचना के बाद करीब एक महीने पहले पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। प्रभारी निरीक्षक

शासन : चल रही जांच, और जो दोषी मिलेंगे उन पर होगी कार्रवाई

प्रमुख सचिव आवास रमेश नितिन गोकर्ण का कहना है कि सरकार की ओर से गठित हाई पावर कमेटी अग्निकांड की तेज गति से जांच कर रही है। सभी दोषियों को चार्जशीट देकर सुनवाई की जा रही है। जांच के दौरान जो अन्य दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

क्या है उपहार कांड

दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में 13 जून 1997 में आग लगने से 69 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। अग्निकांड में मरने वालों के परिवारों को लगभग 25 साल बाद 16 फरवरी 2022 में न्याय मिल सका था।

सतुआ बाबा और महंत बालक दास को राहत, सात साल पुराने प्रतिकार यात्रा मामले में मिली जमानत

वाराणसी। वाराणसी में सात साल पहले प्रतिकार यात्रा के दौरान हुई हिंसा और बवाल में आरोपी महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा और बालक दास को गुरुवार को जमानत मिल गई। एमपी/एमएलए कोर्ट के प्रभारी न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर की। अदालत ने दोनों आरोपियों को 20 हजार के दो जमानतदार देने पर रिहा करने का

आदेश दिया। सात साल पुराने इस मामले में सतुआ बाबा और बालक दास को अदालत में पेश नहीं होनेके कारण फरार घोषित किया गया था। बुधवार को दोनों ने दोनों ने प्रभारी विशेष न्यायाधीश (एमपी—एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत में समर्पण किया था। अदालत ने अंतरिम जमानत देते हुए जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए गुरुवार की तिथि दी थी। दोनो महंत की तरफ से अधिवक्ता एसके द्विवेदी ने कोर्ट में उनका पक्ष रखा और मामला शांति भंग का बताया। कोर्ट ने कहा कि मामले में आरोपियों की कोई विशेष सहभागिता नहीं है। विडियोग्राफी और फोटोग्राफी में भी कोई सहभागिता नहीं है। अन्य आरोपियों की जमानत हो गई है। ऐसे में इन आरोपियों की भी जमानत मंजूर की जाती है।

ये है पूरा मामला

गंगा में गणेश प्रतिमा विसर्जन करने पर अड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, सतुआ बाबा और महंत बालक दास ने पांच अक्तूबर 2015 को मैदागिन स्थित टाउनहॉल मैदान से प्रतिकार यात्रा निकाली थी। यात्रा के दौरान गोदौलिया चौराहे पर बवाल हुआ था। आगजनी की गई थी। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। साथ ही मुकदमा दर्ज करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने मामले की विवेचना की और कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। पुलिस ने सतुआ बाबा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद व महंत बालक दास समेत कई लोगों को जिम्मेदार ठहराया। सुनवाई के दौरान ही अविमुक्तेश्वरानंद ने अग्रिम जमानत की अर्जी डाली थी। विचार के बाद कोर्ट ने जमानत दे दी। अब सतुआ बाबा और महंत बालक दास को भी जमानत मिल गई।

पुआल की ढेर में मिला क्षत-विक्षत शव, अंगों को नोच रहे थे कुत्ते, नजारा देख ग्रामीणों में सनसनी

बलिया। यूपी के बलिया जिले के उकछी गांव में गुरुवार सुबह युवक का क्षत—विक्षत शव पुआल की ढेर में मिला। शव को आवारा कुत्तों से नोंचते देख ग्रामीणों में खलबली मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षत—विक्षत शव को कब्जे में लिया। घटना को लेकर तरह—तरह की चर्चा है। पकड़ी थाना क्षेत्र के उकछी गांव में बस्ती से कुछ दूर रखे पुआल की ढेर के पास से दुर्गंध आ रही थी। ग्रामीणों ने गुरुवार सुबह देखा कि कुछ कुत्ते किसी चीज को नोच रहे हैं। पास जाकर देखा तो सन्न रह गए। कुत्ते किसी शव को नोच कर खा रहे थे। कंकाल को इधर—उधर लेकर भाग रहे थे। देखते ही देखते पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों के अनुसार देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शव के ऊपर पुआल का ढेर लगा हुआ था। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षत—विक्षत शव को पूरी तरह

से बाहर निकलवा कर उसके बिखरे पड़े कंकालों एवं अन्य अंग के अवशेषों को इकट्ठा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पकड़ी थाना प्रभारी निरीक्षक शत्रुन कुमार ने बताया कि सम्भवतः यह शव किसी विक्षिप्त व्यक्ति का प्रतीत हो रहा है। आशंका है कि भीषण ठंड से बचने के लिए पुआल की ढेर में घुस गया हो और उसी में उसकी मौत हो गई हो। मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की बाद ही हो पाएगा। अभी इसकी शिनाख्त का प्रयास करते हुए आगे की जांच की जाएगी।

बिजली विभाग के ठेकेदार के गोदाम में लगी आग, करीब एक लाख का केबल जला

जौनपुर। जौनपुर शहर स्थित महिला थाने के सामने एक किराए के मकान में एक कमरा लेकर गोदाम बनाया गया था। उसमें बिजली विभाग के एक ठेकेदार का सामान रखा गया था। गुरुवार दोपहर करीब 12 अचानक आग लग गई। इससे करीब एक लाख रुपये का सामान जलकर राख हो गया। अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बिजली विभाग का एक ठेकेदार विद्युतीकरण कराने के लिए केबल मंगाया था। उसने किराए का कमरा लेकर गोदाम बनाया। उसमें करीब एक लाख रुपये का केबल रखा था। गुरुवार दोपहर अचानक कमरे के अंदर से धुआं निकलने लगा। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और ठेकेदार को दी। जब तक लोग पहुंचते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। बड़ी घटना न होने पाए इसके लिए तत्काल आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई गई। टीम ने आग पर काबू पाया। सीओ सिटी कुलदीप कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। आग लगने का कारण साफ नहीं है।

सड़क निर्माण नहीं होने से खफा तुलसीपुर बड़ी गैबी में प्रदर्शन , कहा— निकाय चुनाव का करेंगे बहिष्कार

वाराणसी। वाराणसी के तुलसीपुर बड़ी गैबी मार्ग पर सड़क निर्माण नहीं होने से खफा स्वराज संस्था एवं सावित्रीबाई फुले मंच ने गुरुवार को नागरिकों संग प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि सड़क नहीं बनी तो आगामी निकाय चुनाव में जनता मतदान का विरोध करेगी। स्वराज संस्था के प्रबंधक सचिव विकास चंद तिवारी और सावित्रीबाई फुले मंच के संयोजक राजकुमार टुनटुन के संयुक्त नेतृत्व में क्षेत्रीय नागरिकों ने बड़ी गैबी—तुलसीपुर मार्ग पर प्रदर्शन किया। नागरिकों ने आरोप लगाया कि शिकायत के बाद भी सड़क निर्माण नहीं किया गया। महापौर मृदुला जायसवाल ने मार्च 2019 में क्षेत्रीय पार्षद इंद्रदेव पटवा के समक्ष कहा था कि इस रोड को बनवा दिया जाएगा। यह वार्ड दो पार्षदों के बीच में आता है। एक तुलसीपुर की पार्षद कौशल्या जायसवाल, दूसरे पार्षद इंद्रदेव पटवा हैं। बावजूद इसके वहां सफाई व्यवस्था नहीं होती है। सड़क अभी तक नहीं बनाया गया। जिससे लोगों में आक्रोश है। प्रदर्शन में विजय कुमार, लल्लू प्रसाद, लखविंदर भाई, आदि मौजूद रहे।

यूपी में आने वाले दिनों में पड़ेगी हाड़ कंपाती हुई ठंड, राजधानी में हो सकती है बारिश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हाड़ कंपाती हुई ठंड पड़ रही है। लखनऊ मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी लखनऊ में अभी एक सप्ताह तक गलन और बढ़ेगी। इसके साथ ही बर्फीली हवाओं का चलना भी तेज हो सकता है। लखनऊ के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश भी हो सकती है। यही नहीं घना कोहरा भी अभी बना रहेगा। करीब एक हफ्ते बाद लखनऊ में मौसम हल्का साफ होगा। हल्की धूप खिलेगी लेकिन बर्फीली हवाओं की वजह से कोई भी राहत अभी जनवरी भर नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने भी 7 जनवरी तक प्रदेश के 27 जिलों में घने कोहरे और शीत दिन के लिए चेतावनी जारी की है। 31 जिलों में कोहरे से सचेत के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आंचलिक मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक एम. निदेशक के अनुसार बंगाल की खाड़ी के साथ पहाड़ों से भी हवा प्रदेश की ओर चल रही है। इस कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीत दिन के साथ दिन के तापमान में अधिक बदलाव नहीं हो रहा है। दिनभर धुंध बनती दिख रही है। बर्फीली हवा चलने से गलन महसूस होगी। तीन दिन के बाद अधिकतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी नजर आ सकती है। वहीं रात में पारा गिर सकता है। बात करें लखनऊ में आज अधिकतम तापमान की तो गुरुवार को लखनऊ में अधिकतम तापमान करीब 14 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि गुरुवार को सुबह घने कोहरे की चादर लखनऊ पर इस कदर चढ़ी हुई थी कि सुबह के वक्त दफ्तर जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से लखनऊ में रैन बसेरों की व्यवस्था कर दी गई है ताकि कोई भी खुले में न सोए। इसके अलावा जगह—जगह अलाव की व्यवस्था की गई है, ताकि लोगों को सर्दी से बचाया जा सके। मौसम विभाग के अनुसार, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, बरेली, हरदोई, संभल, बदायूं, अमरोहा, शाहजहांपुर, सीतापुर, जालौन, झांसी, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर और आसपास के इलाकों में सर्दी का सितम जारी रहने की संभावना बनी हुई है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, 7 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक रह सकता है वहीं अधिकतम यह 21 डिग्री तक जाने की संभावना है।

कल्याण सिंह का प्रेरणादायी जीवन हम सभी के लिए अनुकरणीय : योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. कल्याण सिंह की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लोकप्रिय जननेता, सुशासन के संवाहक, श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के अग्रदूत, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पद्म विभूषण कल्याण सिंह की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित बाबू जी का प्रेरणादायी जीवन हम सभी के लिए अनुकरणीय है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान व हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एवं पद्म विभूषण से सम्मानित कल्याण सिंह बाबूजी की जयंती पर उन्हें नमन किया है।केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गरीबों, वंचितों एवं पिछड़ों को विकास की मुख्यध ाारा से जोड़ने तथा उनका उत्थान करने के लिए आपको सदैव स्मरण किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने ट्वीट किया कि श्रीराम जन्मभूमि के आंदोलन के अग्रणी नायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बाबूजी ने सेवा, सुशासन एवं सामाजिक न्याय के लिए जो अतुलनीय आदर्श स्थापित किए हैं, वो सदैव प्रेरणादायक रहेंगे।लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया ने लखनऊ नगर निगम के सामने लगी कल्याण सिंह की प्रतिमा पर पुष्पार्चन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

दम घुटने से मासूम की मौत और तीन अचेत, ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सोया था परिवार

वाराणसी। ठंड से बचने के लिए अंगीठी का सहारा ले रहे परिवार के साथ दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। वाराणसी के दरेखू गांव में ठंड से बचने के लिए कोयले की अंगीठी जलाकर कमरे में सो रहे एक ही परिवार के चार लोग गुरुवार सुबह अचेत मिले। आननफानन चारों को अस्पताल ले जाया गया। जहां मासूम को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं दंपती और एक बच्चे का उपचार जारी है।घटना के बाद से गांव में मातम छाया हुआ है।

जौनपुर के चंदवक निवासी राहुल निषाद (32) वाहन चालक है। वो अपनी पत्नी रिंकी (30), दो बच्चों अनुज(5) और डुग्गू (2) के साथ दरेखू गांव मे सोमारु सिंह के मकान मे किराए पर रहता है। बुधवार रात खाना खाने के बाद राहुल निषाद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सोन चला गया। ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाया था।

सुबह काफी देर तक कमरा बंद होने पर बगल के किराएदार ने दरवाजे पर दस्तक दी। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अनहोनी की आशंका में दरवाजे को धक्का देकर लोगों ने खोला। अंदर का नजारा देख सभी सन्न रह गए। कमरे में हल्का धुआं था और चारों लोग एक ही बिस्तर पर अचेत थे। लोहे की कढ़ाई में कोयला और लकड़ी जलाया गया था।

एक जनवरी को भी हुई थी तीन लोगों की मौत

लोगों ने एंबुलेंस के साथ ही रोहनिया पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची एंबुलेंस से चारों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों ने डुग्गू (2) को मृत घोषित क दिया। वहीं राहुल, उसकी पत्नी पिंकी और पांच वर्षीय बच्चे अनुज को भर्ती कर इलाज शुरू किया। गुरुवार सुबह घटना की जानकारी के बाद गांव में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पुलिस मौके पर पहुंची है। बता दें कि इससे पहले एक जनवरी को काशी स्टेशन पर तैनात रेलकर्मी, उनकी पत्नी और ढाई साल का बच्चा मृत हाल में मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पचा चला कि दम घुटने से तीनों की मौत हुई थी। वो भी रात में अंगीठी जलाकर सोए थे।

विधान परिषद की पांच सीटों पर नामांकन आज से, 30 जनवरी को होगा मतदान

लखनऊ। यूपी में 30 जनवरी को होने वाले विधान परिषद चुनाव को लेकर गुरुवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरु हो गई है। यह चुनाव MLC के 5 सीटो पर होना है। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने 29 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया था. जिन सीटों पर चुनाव होना है, उनमें गोरखपुर—फैजाबाद खंड स्नातक,कानपुर खंड और बरेली—मुरादाबाद खंड स्नातक का समेत तीन खण्ड स्नातक और खण्ड शिक्षक क्षेत्र की सीटें शामिल हैं। बता दें कि इस चुनाव की अधि ासूचना गुरुवार को जारी हुई. इसके बाद से उम्मीदवार आज से ही नामांकन कर सकेंगे. नामांकन पत्र जमा करने का अंतिम दिन 12 जनवरी है। इसके बाद 13 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं उम्मीदवार 16 जनवरी तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद 30 जनवरी को सभी पांच सीटों पर मतदान कराया जाएगा। मतदान का समय सुबह 8.00 से शाम 4.00 बजे तक होगा। मतगणना का काम दो फरवरी को होगा। गोरखपुर—फैजाबाद खंड स्नातक, कानपुर खंड स्नातक, बरेली—मुरादाबाद खंड स्नातक, इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक और कानपुर खंड शिक्षक की सीट शामिल है। जिन सदस्यों का कार्यकाल 12 फरवरी को खत्म हो रहा है, उसमें गोरखपुर—फैजाबाद खण्ड स्नातक सीट से देवेंद्र प्रताप सिंह, कानपुर खण्ड स्नातक सीट से अरुण पाठक, बरेली—मुरादाबाद खण्ड स्नातक सीट से डॉ.जयपाल सिंह व्यस्त का नाम शामिल है। वहीं इलाहाबाद—झांसी खण्ड शिक्षक से सुरेश कुमार त्रिपाठी और कानपुर खण्ड शिक्षक सीट से राजबहादुर सिंह चंदेल का भी कार्यकाल 12 फरवरी को पूरा हो रहा है।

यूपी बोर्ड स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया में बदलाव,पहले मिलेगी तीन साल की मान्यता, फिर होगा नवीनीकरण

लखनऊ। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों की मान्यता अब तीन साल के लिए दी जाएगी। बाद में मान्यता शर्तों को पूरा करने के बाद पांच साल के लिए इसका रिन्यूअल किया जाएगा। शासन से स्वीकृत नई मान्यता की शर्तों में निर्धारित है। पहले मान्यता के लिए स्थलीय निरीक्षण में व्यवस्था थी कि दिवस, भवन के समक्ष खड़े होकर अपना और भवन का फोटो खिंचवाकर रिपोर्ट के साथ संलग्न करेंगे। अब जनपदीय समिति विस्तृत निरीक्षण करेगी। समिति द्वारा निरीक्षण के समय विद्यालय भवन, प्रयोगशाला, खेल के मैदान, बाउंड्रीवाल, पुस्तकालय की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की जाएगी। इसे परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा नई शर्तों में विद्यालय में छात्र–शिक्षक अनुपात 40रू01 से अधिक नहीं होगा। प्रत्येक विषय का एक शिक्षक होना अनिवार्य होगा। विद्यालय द्वारा लिए जा रहे शिक्षण शुल्क का लेखाजोखा रखा जाएगा। शिक्षण शुल्क में से कम से कम 70 प्रतिशत शैक्षिक व अन्य कर्मियों की परिलब्धियों पर खर्च होगा। इसके अलावा अब शिक्षकों, छात्रों की उपस्थिति बोर्ड की वेबसाइट पोर्टल पर प्रत्येक कार्यदिवस में दर्ज करनी होगी। स्कूल की वेबसाइट पर ईमेल, फोन नंबर के अलावा आधारभूत सुविधाओं जैसे भवन, कक्षों की संख्या, कंप्यूटर, खेल, पुस्तकालय, लाइट, पंखे आदि का विवरण दिया जाएगा। योग्यता सहित शिक्षकों का विवरण, कक्षावार छात्र, छात्राओं की संख्या, प्रत्येक वर्ष का परीक्षाफल व शुल्क का विवरण भी प्रदर्शित करना होगा। पानी के लिए सबमर्सिबल, आरओ, पाइप पेयजल, ओवरहेड टैंक, हैंडवाश प्लेटफार्म, अलग–अलग आयु वर्ग के बच्चों की लंबाई के हिसाब से अलग–अलग ऊंचाई के प्लेटफार्म की व्यवस्था करनी होगी। छात्र, छात्राओं के अलग–अलग शौचालय के अलावा दिव्यांगों के लिए विशेष इंतजाम करने होंगे। पहले छात्र संख्या के अनुसार सिर्फ शौचालय व पीने के पानी के लिए हैंडपंप या अन्य कोई समुचित व्यवस्था की शर्त थी। अब मान्यता 30 वर्ष की रजिस्टर्ड लीज डीड पर भी दी जा सकेगी। कई अन्य मानक भी परिवर्तित हुए हैं।

शिक्षा मंत्रालय पहुंचा AMU कर्मियों का मामला,यूनिवर्सिटी ने कर्मचारियों को स्थाई करने का प्रस्ताव भेजा

अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयम में दशकों से काम कर रहे अस्थाई कर्मचारियों का मामला अब शिक्षा मंत्रालय और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन तक पहुंच चुका है। एएमयू के अधिकारियों का पैनल इस मामले में दिल्ली पहुंचा और मंत्रालय के सामने कर्मचारियों की बात रखी। एएमयू के अधिकारियों ने मंत्रालय और यूजीसी के सामने अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने का प्रस्ताव रखा है। जिससे कि कर्मचारियों की समस्या का स्थाई समाधान निकाला जा सके। अधिकारियो से मिलने के बाद यूनिवर्सिटी का पैनल अलीगढ़ वापस लौट आया है। अधिकारियों की माने तो उन्हें आश्वासन मिला है कि जल्दी ही कर्मचारियों को राहत दी जाएगी। एएमयू में काम करने वाले अस्थाई कर्मचारियों का कांट्रैक्ट रिनीवल नहीं किय जा रहा था। जिसके बाद कर्मचारियों ने 30 और 31 दिसंबर को प्रशासनिक भवन के बाहर घंटों तक हंगामा और नारेबाजी के बाद वीसी प्रो. तारीक मंसूर ने कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की थी। जिसके बाद उन्होंने कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि जल्दी ही उन्हें राहत दी जाएगी। जिसके बाद अब यूनिवर्सिटी ने जून 2023 तक के लिए कर्मचारियों का करार बढ़ा दिया था और उन्हें दिसंबर का वेतन भी जारी करने के आदेश दे दिए थे। अब उन्हें स्थाई रहात दी जा सके, इसके लिए यूनिवर्सिटी ने मंत्रालय और यूजीसी के प्रस्ताव भेजा है। एएमयू में लगभग लगभग 8000 का नॉन टीचिंग स्टाफ है। इसमें ज्यादातर अस्थाई कर्मचारी हैं, जिनसे कांट्रेक्ट बेस पर काम कराया जाता है। हर साल इनके करार रिनीवल किए जाते हैं। इन कर्मचारियों को 14 हजार से लेकर 60 हजार रुपए तक वेतन मिल रहा है और कर्मचारी 20–20 साल से नौकरी कर रहे हैं। इन कर्मचारियों में लगभग 1600 कर्मचारी ऐसे थे, जिनके कांट्रैक्ट रिनीवल नहीं किए गए थे। इसी के विरोध में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और इंतजामिया के सामने अपनी मांगे रखी। कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखते हुए यूनिवर्सिटी के उच्च अधिकारियों ने अपनी बैठक करके उनके करार रिनीवल करके उन्हें राहत दी थी। एएमयू में 1700 का टीचिंग स्टाफ है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में लगभग 8000 का नॉन टीचिंग स्टाफ कार्यरत है। सरकार ने अब यूनिवर्सिटी को निर्देश दिए हैं कि उन्हें 1700 के टीचिंग स्टाफ के साथ 2000 नॉन टीचिंग स्टाफ का ही भुगतान किया जाएगा। जिसके बाद यूनिवर्सिटी में कर्मचारियों के वेतन का संकट खड़ा हो गया है। क्योंकि सरकार से सिर्फ 2000 नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए ही वेतन स्वीकृत हुआ है। यही कारण है कि यूनिवर्सिटी कर्मचारियों के कांट्रैक्ट रिनीवल नहीं कर रही है और छंटनी की तैयारी शुरू की थी।

गरीब का पैर कटने से बचाया विधायक रोमी साहनी ने कायम की मानवता की मिसाल

इलाज हेतु 55000 रुपये की दी आर्थिक सहायता

अवध की आवाज

लखीमपुर खीरी। पलिया के मोहल्ला बरबंडा निवासी गरीब ठेलिया चालक माखन के बेटे दिनेश का अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो

गया था जिसमे उसका एक हाथ व एक पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, ऐसे में डॉक्टरों ने भी पैर काटने की सलाह दे दी थी। इसकी सूचना जब मोहल्ले के लोगों ने विधायक रोमी साहनी जी को दी उस पर विधायक रोमी साहनी जी ने तुंरत उस गरीब को लखनऊ के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया और इलाज का खर्चा खुद उठाने का वादा करते हुये अस्पताल पहुँच कर तुरन्त 55000 रुपये देकर उसका इलाज शुरू करवाया। यह भी उम्मीद है कि अब शायद उसका पैर काटना नही पड़ेगा। इस मानवीय कार्य से क्षेत्रवासियों की हर मुसीबत में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले पलिया विधायक रोमी साहनी जी की प्रशंसा पलिया नगर के साथ ही पूरे क्षेत्र में हो रही है।

महिला पर जानलेवा हमला, लहूलुहान हालात में मरा समझ भागा बदमाश

अलीगढ़। जिले के महुआखेड़ा इलाके में चल रहे एक जमीनी विवाद में महिला को गोली मारकर घायल कर दिया गया। महिला मंदिर में पूजा करने गई थी, इसी दौरान आरोपी वहां आए और महिला को गोली मार दी। जिसके बाद महिला लहूलुहान होकर गिर पड़ी। गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजनों ने महिला को बेहोशी की हालत में श्रछ मेडिकल कालेज में भर्ती कराया है। महुआखेड़ा के याकूतपुर गांव निवासी राजेश देवी का उनके गांव के ही एक व्यक्ति शिवा के साथ जमीनी विवाद चल रहा है। जिसके चलते कई बार दोनों पक्षों में झगड़ा हो चुका है। बुधवार रात को महिला अपने घर के पास मंदिर गई थी और पूजा करके वापस लौट रही थी। आरोप है कि इसी दौरान गांव में ही रहने वाला शिवा वहां आ गया। उसने तमंचे से महिला के ऊपर फायर झोंक दिया। गोली लगने से महिला की चीख निकल गई और महिला लहूलुहान होकर वहीं पर गिर पड़ी। महिला काफी देर तक घर नहीं पहुंची तो परिजनों को संदेह हुआ, जिसके बाद वह उसकी खोज में निकले। अब पुलिस आरोपी की तलाश में छापामारी कर रही है। उसके परिजनों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। इंस्पेक्टर विजयकांत शर्मा ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आरोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है, जल्दी ही आरोपी पुलिस की हिरासत में होगा।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों का होगा विकास

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन से अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास योजनाओं को प्रदेश में एक नई गति मिली है। वहीं प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में (1218) परियोजनाएं निर्माणाधीन है। जिसमें पॉलीटेक्निक, आईटीआई, डिग्री कॉलेज, इन्टर कॉलेज, यूनानी मेडिकल कॉलेज, पाइप पेयजल योजना, सद्भाव मण्डप प्रमुख हैं। इन परियोजनाओं में से (622) परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए अपर मुख्य सचिव मोनिका एस गर्ग के निर्देशन में माह अक्टूबर व नवम्बर में मण्डल स्तर पर समीक्षा बैठकें आयोजित की गयी। लगभग 350 ऐसी परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं, जिन्हें विशेष ध्यान देकर इसी वर्ष में पूर्ण कराया जाएगा। साथ ही अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में मौजूदा वित्तीय वर्ष में अब तक 4 पॉलीटेक्निक, 1 आईटीआई, 4 राजकीय इन्टर कॉलेज, 4 पेयजल योजना, 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को पूर्ण कर जनोपयोगी बनाया जा चुका है। धर्मपाल सिंह ने बताया कि अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से 30 राजकीय इन्टर कॉलेज, 120 पेयजल योजनाएं, 5 पालीटेक्निक व आईटीआई, 2 कस्तूरबा गाँधी विद्यालय, 10–12 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 3 छात्रावास पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 4 होम्योपैथिक चिकित्सालय, 80 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 20 शौचालय ब्लाक पूर्ण कराये जाने हेतु विभाग कार्य किया जा रहा हैं।

नौकरी के नाम पर महिला से सामूहिक दुष्कर्म

अलीगढ़। जिले के इगलास थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि एक बाइक एजेंसी के शोरूम मालिक नौकरी के नाम पर उसके साथ पिछले कई महीनों से सामूहिक दुष्कर्म कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। जब महिला ने इसका विरोध करना चाहा तो आरोपियों ने उसे धमकाया और उसके बच्चे को भी जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद महिला शांत हो गई और चुपचाप सब सहती रही। जब वह किसी तरह बचकर निकली तो उसने मामले में पुलिस ने न्याय की गुहार लगाई है। गुरुवार को महिला एसएसपी से मिलने आई थी, लेकिन उसकी मुलाकात नहीं हो सकी। पीड़ित महिला ने बताया कि वह खैर की रहने वाली है। उसने बताया कि दोनों आरोपी सगे भाई हैं और उनकी बाइक एजेंसी है। वह उसे नौकरी का झांसा देकर खैर से लेकर आए थे। जिसके बाद कुछ दिन उन्होंने उसे अपनी एजेंसी में ही रखा और फिर एक किराए के मकान में रख दिया। इसके बाद दोनों आरोपियों ने उसके साथ बारी–बारी से दुष्कर्म किया। जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसे और उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी दी। एक दिन तो आरोपियों ने उसके बेटे के सिर पर तमंचा भी रख दिया। इस कारण वह शांत रही और आरोपी उसका लगातार शोषण करते रहे। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसका पति नशेड़ी किस्म का था और कई साल पहले ही कहीं चला गया था। इसके बाद वह खुद ही अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही है। खैर में उसका एक मकान था, इस पर भी आरोपियों की नजर थी। आरोपियों ने उसे झांसे में लेकर मकान भी ठग लिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने अपने किसी रिश्तेदार के नाम उसके मकान का बयनामा करा दिया, जिसके बाद वह सड़क पर आ गई है। उनसे क्षेत्रिय थाने में शिकायत की, मगर कई दिन चक्कर लगाने के बाद भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। जिसके बाद वह एसएसपी से मिलने आई थी, लेकिन उसकी मुलाकात नहीं हो सकी। अब वह दुबारा आएगी। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है। शिकायत आने पर मामले की जांच कराकर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डीएम ने सदर तहसील का किया औचक निरीक्षण,राजस्व वसूली कम मिलने पर जताई नाराजगी

बांदा। डीएम दीपा रंजन ने सदर तहसील का गुरुवार को निरीक्षण किया। जहां राजस्व वसूली कमजोर मिली। इसे बढ़ाने के लिए उन्होंने कड़ी हिदायत दी। उन्होंने विभिन्न पटलों, अभिलेखागार, कम्प्यूटरीकृत नामांकन पंजिका, राजस्व वाद रजिस्टर, भूलेख कम्प्यूटर केन्द्र, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार कोर्ट, पेंशन एवं कर्मचारियों से सम्बन्धित प्रकरण आदि की जानकारी ली और सभी को समय से निस्तारित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने राजस्व वादों के निस्तारण किये जाने। अमलदरामद के परवाना जारी करने का रजिस्टर देखा। समय से राजस्व वादों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिये। उन्होंने तहसील स्तर से जारी किये जाने वाले विभिन्न प्रमाण पत्रों को समय से जारी करने और जन शिकायतों का गुणवत्ता एवं समय बद्धता से निपटारे के निर्देश दिये। बड़े बकायेदारों का वसूली रजिस्टर भी देखा। अमीनों के द्वारा वसूली कराये जाने और बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिये। राजस्व वसूली कम पाये जाने पर लक्ष्य पूर्ति को कहा। डीएम ने निरीक्षण में भूलेख अभिलेखागार में ग्राम वार रखे राजस्व अभिलेखों का निरीक्षण किया। कम्प्यूटरीकृत खसरा, खतौनी पटल के अवलोकन में आवेदकों से वार्ताकार खतौनी जारी करने को कहा।उन्होंने वरासत के मामलों का समय बद्धता के साथ निस्तारण के निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी उमाकान्त त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी सदर सुरभी शर्मा, तहसीलदार सदर पुष्पक सहित सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी गण उपस्थित रहे।

तुनिषा शर्मा के नाम शीजान की बहन फलक नाज का नोट हुआ वायरल, लिखा कभी नहीं सोचा था

दिवंगत एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा का 4 जनवरी को 21वां जन्मदिन था। इस मौके पर हर कोई एक्ट्रेस को याद करता नजर आया। सभी का मन उदास और आंखें नम दिखीं। वहीं, तुनिषा के सभी दोस्तों ने उन्हें बर्थडे विश करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किए थे। इसी बीच एक्ट्रेस के एक्स बॉयफ्रेंड शीजान खान तो फिलहाल जेल में हैं लेकिन उनकी बहन यानी फेमस एक्ट्रेस फलक नाज का तुनिषा के लिए किया गया पोस्ट जरूर सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें, तुनिषा का फलक नाज से करीबी रिश्ता था। दोनों काफी स्पेशल बॉन्ड शेयर करती थीं। तुनिषा के इंस्टाग्राम पर उनकी और फलक की कई प्यारी तस्वीरें और वीडियो हैं, जिनमे इनका प्यार साफ नजर आ रहा है। हाल ही में ये खबर भी सामने आई थी कि शीजान की बहन फलक नाज ने तुनिषा के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान की थी। हालांकि वो प्लान कभी मुकम्मल नहीं हो सका क्योंकि उससे पहली ही अस्ट्रेजर्स ने अपनी जान दे दी। वहीं, अब तुनिषा शर्मा के बर्थडे के मौके पर फलक नाज से उन्हें याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। फलक ने इंस्टाग्राम पर इमोशनल नोट लिखते हुए तुनिषा के साथ अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की। फलक ने लिखा, टून्नु मेरा बच्चा। कभी नहीं सोचा था कि ऐसे विश करूंगी तुझे, तू जानती थी कि अप्पी ने प्लान किया है तेरे लिए सरप्राइज। मैं तुझे उस प्रीटी प्रिंसेस ड्रेस में देखना चाहती थी, मैं तुझे तैयार करती, तेरा केक बनवाती। तेरा वो सरप्राइज्ड फेस देखना था मुझे। तू जानती है अच्छे से टून्नु तू मेरे लिए क्या मायने रखती है, दिल टूटा हुआ है मेरा बहुत, इतनी तकलीफ कभी महसूस नहीं हुई मुझे, जितनी तेरे जाने के बाद से है। फलक ने आगे लिखा, कभी–कभी समझ नहीं आता कि दुआ किसके लिए करें। तेरी रूह की सुकून के लिए या हमारी (अम्मा, शीजान और मेरी) जिन्दगी के इतने मुश्किल इम्तिहान के लिए। बेचौन रातें, अनदेखे आंसू, तू सब देख रही है। मुझे पता है कि तू मेरे आस–पास ही है। मैं तुझे महसूस कर सकती हूं। हम तुझे हर दिन मिस करते हैं टुन्नू। तुम हमेशा हमारे दिलों में रहोगी। उम्मीद है कि तेरी सुकून वाली तलाश खत्म हो गई हो। मेरा बच्चा, मेरी नन्ही सी जान हैप्पी बर्थडे और आई लव यू टू। अब फलक नाज का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जहां कुछ लोग ये पोस्ट देखकर इमोशनल होते नजर आए तो कुछ लोग फलक नाज को ट्रोल करते भी दिखे। लोगों का कहना है कि ये सब बस अच्छा होने का ड्रामा चल रहा है। ऐसे में सबने अपनी अलग–अलग राय इस पोस्ट पर रखी।

एक्टिंग के साथ बिजनेस में भी चलता है दीपिका पादुकोण का सिक्का, इन कामों से कमाती हैं करोड़ो

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों आने वाली फिल्म पठान को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। इस फिल्म मंप वह शाहरुख खान के साथ नजर आएंगी। दीपिका ने अपनी दमदार एक्टिंग के बल पर आज फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बनाई है। दीपिका बी–टाउन की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस हैं जिनके चाहने वाले देश ही नहीं बल्कि विदेशों में फैले हुए हैं।

बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुकी दीपिका सिर्फ एक्टिंग वर्ल्ड तक ही सीमित नहीं है। दीपिका फिल्मों और विज्ञापनों में अभिनय के अलावा भी बहुत कुछ ऐसा करती हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं है। शायद ही इस बारे में किसी को पता हो लेकिन दीपिका सिर्फ एक्टिंग नहीं करती हैं बल्कि वो एक बिजनेस वुमेन भी हैं। अपनी फिल्मों के साथ–साथ एक्ट्रेस कई साइड बिजनेस भी करती हैं। एक नहीं बल्कि दीपिका ने कई बिजनेस में पैसा लगा रखा है। साल 2007 में फिल्म ओम शांति ओम से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली दीपिका आज वर्ल्ड फेमस एक्ट्रेस हैं। इसी के साथ दीपिका पादुकोण बिजनेस वर्ल्ड में भी उतनी ही सक्सेसफुल हैं और पॉपुलर हैं।

बता दें कि साल 2015 में दीपिका ने अपने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस फाउंडेशन श्द लिव लव लाफश फाउंडेशन की शुरुआत की थी। इसी साल उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर भी चौंकाने वाला खुलासा किया था जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। दीपिका ने बताया था कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थीं। इसी के साथ एक्ट्रेस ने बताया कि इसका सामना उन्होंने कैसे किया। दीपिका ने अपने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस फाउंडेशन के बाद मोर दैन जस्त सैड नाम से एक कैम्पैन की शुरुआत की थी, जिसके तहत डिप्रेशन और एंजायटी के पेशेंट के इलाज के लिए डॉक्टरों अवेलेबल कराए गए। ना सिर्फ मेंटल हेल्थ बल्कि एक्ट्रेस क्लोदिंग लाइन से भी जुड़ी हुई हैं। साल 2013 में उन्होंने क्लोदिंग लाइन की शुरुआत की थी। दीपिका ने अपनी क्लोदिंग लाइन की शुरुआत के बाद मिंत्रा के साथ मिलकर अपने ब्रांड "ऑल अबाउट यू" लॉन्च किया था। आज भी अभिनेत्री ऑनलाइन कपड़ें बेचती हैं। दीपिका ने ड्रूम फूड इंटरनेशनल और ब्लू स्मार्ट नाम की इलेक्ट्रिक टैक्सी के स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट किया था। बात करें उनके के हाल ही में किए स्टार्ट की तो दीपिका पादुकोण ने पिछले दिनो ही 82°E नाम से एक स्किनकेयर लाइन की शुरुआत की है। इन सभी चीजों के अलावा दीपिका पादुकोण अपना प्रोडक्शन हाउस भी चलाती हैं। दीपिका के प्रोडक्शन हाउस का नाम श्का प्रोडक्शन्सश है जिसके बैनर तले अभी तक दो बॉलीवुड फिल्में बन चुकी हैं। दीपिका और विक्रांत मेसी स्टारर छपाक और रणवीर सिंह की फिल्म 83 इन दोनों ही फिल्मों का निर्माण का प्रोडक्शन्स के बैनर तले हुआ है। फिलहाल नई फिल्म द इंटर्न का प्रोडक्शन भी दीपिका ही संभाल रही हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो दीपिका की फिल्म पठान रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है। किंग खान स्टारर पठान 25 जनवरी को थियेटर में रिलीज होगी। इसके अलावा दीपिका फिल्म फाइटर में ऋतिक रोशन के साथ पहली बार स्क्रीन स्पेस शेयर करने वाली हैं। इस फिल्म में अनिल कपूर और करण सिंह ग्रोवर भी अहम रोल में हैं।

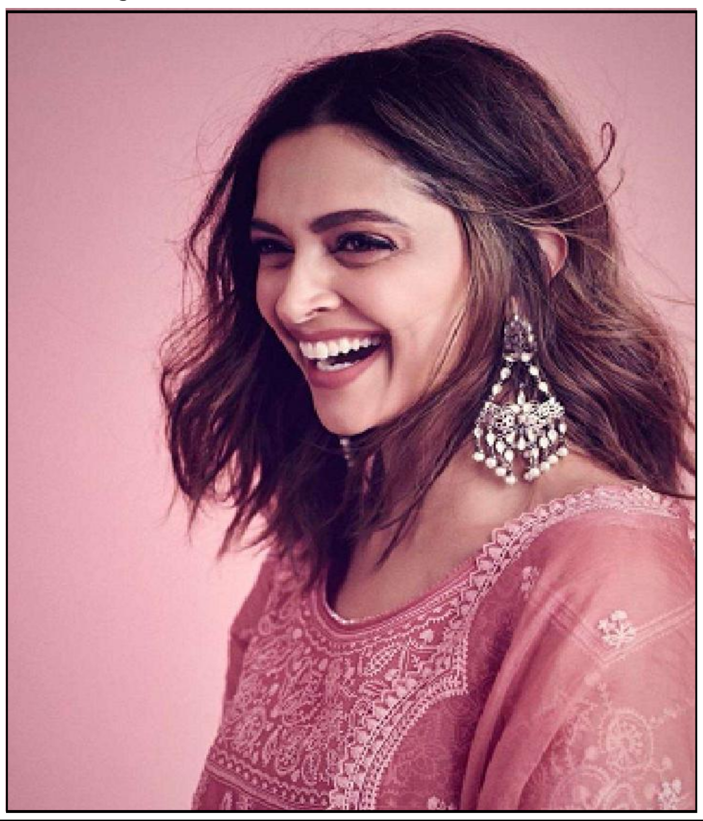

सुशांत सिंह की मौत के ढाई साल बाद घर को मिला नया किराएदार,रेंट जानकर हो जाएंगे हैरान

बॉलीवुड की मिस्टीरियस डेथ में से एक सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की खबर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया हैं। एक्टर भले ही आज इस दुनिया में नहीं हैं,लेकिन उनकी यादें आज भी फैंस के दिलों में जिंदा हैं। सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए ढाई साल हो गए हैं। वही सुशांत की डेथ के बाद से उनका मुंबई वाला फ्लैट आज भी सुना पड़ा हुआ

हैं। लेकिन अब एक्टर के फ्लैट को लेकर एक नयी जानकारी सामने आ रही हैं। दरअसल उड़ती–उड़ती खबरे अब ऐसी सामने आ रही है की सुशांत के फ्लैट को उनकी मौत के करीब ढाई साल बाद नया किराएदार मिल गया है। दरअसल सुशांत के निधन के बाद से उनका फ्लैट खाली पड़ा था। कई लोगों ने इस फ्लैट को देखा लेकिन रहने के लिए कोई राजी नहीं हो रहा था। ऐसे में अब मिली जानकारी के अनुसार एक्टर के इस घर में जल्द ही नए लोग रहने आ रहे हैं। सुशांत मुंबई के बांद्रा स्थित कार्टर रोड पर लग्जरी फ्लैट में किराए पर रहा करते थे। साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान अचानक बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से सनसनी मच गई थी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि, एक्टर ने अपने इसी किराये के मकान में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। हालांकि सुशांत की मौत की मिस्ट्री अभी तक सुलझ नहीं पाई हैं। आज भी उनके इस रहस्यमयी मौत को लेकर नए अपडेट सामने आते रहते हैं।

मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक नए किराएदार को इस फ्लैट के लिए हर महीने लगभग 5 लाख रुपये किराया देना होगा। इतना ही नहीं फ्लैट मालिक को 30 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना होगा। सुशांत इस फ्लैट का एक महीने का 4.5 लाख रुपये किराया देते थे। अब इस फ्लैट के ओनर ने किराया बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। ये फ्लैट 3600 स्क्वॉयर फुट के एरिया में बना हुआ है। इसमें 4 बेडरूम है, जिसके साथ छत भी अटैच है। सुशांत इस फ्लैट में साल 2019 में शिफ्ट हुए थे। बता दें कि हाल ही में सुशांत के पोस्टमार्टम करने वाली टीम के एक मेंबर रूप कुमार ने बड़ा खुलासा किया था। जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि पोस्टमार्टम के समय उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। उन्हें यह कहा गया था कि जल्द से जल्द उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम करें और पुलिस को बॉडी सौंप दें। वही सुशांत के फ्लैट के नए किराएदार मिलने की खबर सुन उनके फैंस काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। ऐसे एक बार बार फिर से सुशांत के फैंस के दिलों में उनकी यादें भी ताजा हो गयी हैं।

अवध की आवाज हिन्दी दैनिक, प्रकाशक ,मुद्रक व स्वामी,अनिल कुमार सिंह द्वारा स्काई लाइन प्रिन्टर्स,119/23 खन्दारी लेन, लालबाग, लखनऊ उ0प्र0 से मुद्रित तथा डी–97/3 व 7,सेक्टर–7, इन्दिरा नगर,लखनऊ,उ0प्र0 से प्रकाशित। सम्पादक अनिल कुमार सिंह फोन : 0522–4340954
R.N.I.- UPHIN/2012/45127
मो0–7905407289, Email: avadhkiaawaz@gmail.com
नोट : समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादोंका न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।